

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 मई 2012—वैशाख 21, शक 1934

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रबर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद में पुरस्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्र. ई-1-38-2012-5-एक.— श्री अनिल कुमार जैन, भाप्रसे (1986) विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश नई दिल्ली तथा आवासीय आयुक्त मध्यप्रदेश नई दिल्ली (अति. प्र.) की सेवावें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को योजना आयोग में सलाहकार के पद (संयुक्त सचिव स्तर) पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती है।

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2012

क्र. ई-5-525-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्री आर. के. चतुर्वेदी, आयएएस., विकअ-सह-आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को दिनांक 7 से 18 मई 2012 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 मई 2012 एवं 19, 20 मई 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. चतुर्वेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन विकअ-सह-आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम तथा मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आर. के. चतुर्वेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. चतुर्वेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-843-आयएएस-लीब-5-एक.—श्री नीरज दुबे, कलेक्टर, जिला शहडोल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 फरवरी 2012 द्वारा दिनांक 16 से 28 अप्रैल 2012 तक, तेरह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

क्र. ई-5-862-आयएएस-लीब-5-एक.—श्री एम. सिबी चक्रवर्ती, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अनूपपुर को दिनांक 26 मार्च 2012 से 9 अप्रैल 2012 तक पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. सिबी चक्रवर्ती को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एम. सिबी चक्रवर्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. सिबी चक्रवर्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2012

क्र. ई-5-560-आयएएस-लीब-एक-5.—श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएएस., सचिव मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग को दिनांक 27 अप्रैल 2012 से 5 मई 2012 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 मई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-674-आयएएस-लीब-एक-5.—श्री एस. के. मिश्रा, आयएएस., तत्का. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम

एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2012 के द्वारा दिनांक 9 से 16 अप्रैल 2012 तक, आठ दिन के स्वीकृत एक्स इंडिया अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 17 अप्रैल 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2012 की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी।

क्र. ई-5-826-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस., कलेक्टर, जिला डिण्डौरी को दिनांक 23 से 27 अप्रैल 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि की अवकाश अवधि में श्री ए. पी. सिंह, अपर कलेक्टर, जिला डिण्डौरी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन कलेक्टर, जिला डिण्डौरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि द्वारा कलेक्टर जिला डिण्डौरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ए. पी. सिंह, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती।

क्र. ई-5-867-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री तरुण कुमार पिथोड़े, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी डबरा, जिला ग्वालियर को दिनांक 23 से 28 अप्रैल 2012 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 अप्रैल 2012 एवं 29 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री तरुण कुमार पिथोड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अनुविभागीय अधिकारी, डबरा, जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री तरुण कुमार पिथोड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता है।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरुण कुमार पिथोड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2012

क्र. ई-5-425-आयएएस-लीब-5-एक.—श्री मनोज गोयल, आयएएस., प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर को दिनांक 14 से 30 मई 2012 तक सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 मई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज गोयल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मनोज गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-810-आयएएस-लीब-एक-5.—श्रीमती पुष्पलता सिंह, आयएएस., संचालक, ग्रामीण रोजगार को दिनांक 30 अप्रैल 2012 से 5 मई 2012 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 29 अप्रैल 2012 एवं 6 मई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पुष्पलता सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, ग्रामीण रोजगार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती पुष्पलता सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पुष्पलता सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

No. E-5-502-IAS-Leave-5-I.—Sanction is hereby accorded to Dr. J. T. Ekka, IAS (1986) Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Jail Department to avail

ex-India earned leave of 16 days from 13th June, 2012 to 28th June, 2012.

(2) Shri J. N. Kansotia, IAS (1989), Secretary, Government of Madhya Pradesh, Higher Education Deptt., shall hold the additional charge of Jail Department, during the leave period of Dr. J. T. Ekka.

(3) On return from leave Dr. J. T. Ekka is again posted as Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Jail Department, temporarily, until further orders.

(4) Shri J. N. Kansotia, IAS (1989), Secretary, Government of Madhya Pradesh, Higher Education Department shall be relieved from the additional charge of Jail Department after DR. J. T. Ekka Joins the post on return from leave.

(5) Dr. J. T. Ekka will be entitled to draw leave salary and other allowances on the same rates he was getting before proceeding on leave.

(6) It is certified that had Dr. J. T. Ekka not proceeded on leave, he would have continued on this post.

भोपाल, दिनांक 1 मई 2012

क्र. ई-5-907-आयएएस-लीब-5-एक.—श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, आयएएस., अपर संचालक, नर्मदा धाटी विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश इंदौर को दिनांक 5 से 11 मई 2012 तक सात दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12, 13 मई 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर संचालक, नर्मदा धाटी विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद कुमार गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवनि वैश्य, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2012

क्र. ई-1-152-2012-5-एक.—श्री आर. परशुराम, भाप्रसे (1978), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय को दिनांक 1 मई, 2012 से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन नियुक्त किया जाता है।

क्र. ई-1-145-2012-5-एक.—राज्य शासन श्री अवनि वैश्य, भाप्रसे. (1975), मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन को अधिवार्षिकों आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 30 अप्रैल, 2012 (अपराह्न) से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विजया श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव “कार्मिक”।

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2012

क्र. 367-418-2012-सूअप्र-एक-9.—राज्य शासन, एतद्वारा माननीय श्री इकबाल अहमद, माननीय सूचना आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, को पूर्व में स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 11 से 20 अप्रैल 2012 तक (10 दिवस) एवं दिनांक 21, 22 अप्रैल 2012 का शासकीय अवकाश को निरस्त करते हुए दिनांक 13, 16, 17 व 18 अप्रैल, 2012 (04 दिवस) का आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 14, 15 अप्रैल 2012 को सार्वजनिक अवकाश के साथ

दिनांक 13 अप्रैल 2012 से 19 अप्रैल 2012 तक मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश कौल, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2012

क्र. ई-5-900-आयएएस-लीव-एक-5.—श्री आनन्द कुमार शर्मा, आयएएस., अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 मार्च 2012 द्वारा दिनांक 26 से 31 मार्च 2012 तक, छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

क्र. ई-5-558-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री विनोद कुमार, आयएएस., श्रम आयुक्त, म. प्र. इन्डौर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2012 द्वारा दिनांक 21 से 31 मार्च 2012 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, मैं आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 21 मार्च 2012 से 2 अप्रैल 2012 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मार्च 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
क्षी. एस. तोमर, अवर सचिव “कार्मिक”।

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्र. ई-1-147-2012-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

#### तालिका

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अनुपम राजन (1993), संचालक, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश।	संचालक, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम।	अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन

(1)	(2)	(3)	(4)
2	श्री डी. डी. अग्रवाल (1995), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम एवं मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेई बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन.	आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी बाजपेई बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन.	संभागीय कमिशनर

2. श्री आकाश त्रिपाठी, भाप्रसे (1998), अपर सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 01 मई, 2012

क्र. ई-1-19-2012-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे, के अधिकारियों को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता हैः—

### तालिका

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती अजिता बाजपेई पाण्डे (1981), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विकास विभाग.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.	अध्यक्ष राजस्व मंडल
2	श्रीमती अमिता शर्मा (1981), विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्यप्रदेश नई दिल्ली तथा आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश नई दिल्ली (अतिरिक्त प्रभार).	विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्यप्रदेश नई दिल्ली तथा आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश, नई दिल्ली (अतिरिक्त प्रभार).	अध्यक्ष राजस्व मंडल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विजया श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव “कार्मिक”.

**गृह विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2012**

क्र. एफ-1 (ए) 54-2000-ब-2-दो.—श्री कमल सिंह राठौर, भापुसे, उपपुलिस महानिरीक्षक, जे.एन.पी.ए. सागर को दिनांक 19 अप्रैल 2012 से 3 मई 2012 तक, कुल पन्द्रह दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री कमल सिंह राठौर, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य पुलिस अधीक्षक, पी.टी.एस. मकरोनिया परिसर, जे.एन.पी.ए. सागर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कमल सिंह राठौर, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपपुलिस महानिरीक्षक, जे.एन.पी.ए. सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री कमल सिंह राठौर, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, जे.एन.पी.ए. सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव पुलिस महानिरीक्षक (सर्तकता), अ.अ.वि., पु.मु. भोपाल के कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री कमल सिंह राठौर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कमल सिंह राठौर, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्र. एफ-1 (ए) 399-1988-ब-2-दो.—श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (सर्तकता), अ.अ.वि. पु.मु. भोपाल को Mid Career Training Programme Phase-V में दिनांक 9 अप्रैल 2012 से 27 अप्रैल 2012 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 30 अप्रैल 2012 से दिनांक 5 मई 2012 तक यू. के. में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 7 से 10 मई 2012 तक, कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex-India) दिनांक 6 मई 2012 (रविवार) के विज्ञप्ति अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

- विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं।

- विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality) स्वीकार नहीं करेंगे।
- विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (सर्तकता), अ.अ.वि. पु. मु. भोपाल का कार्य श्री के. बाबूराव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि. पु.मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (सर्तकता) अ.अ.वि., पु.मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव पुलिस महानिरीक्षक (सर्तकता), अ.अ.वि. पु. मु. भोपाल के कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सी. व्ही. मुनिराजू, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2012

क्र. एफ-1(ए) 28-2009-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 फरवरी 2012 द्वारा श्रीमती रूचिका जैन जिंदल, भापुसे, सेनानी 17वीं वाहिनी, विसबल, भिण्ड को दिनांक 26- नवम्बर 2011 से 24 मार्च 2012 तक, कुल एक सौ बीस दिन की चार्झल्ड केयर लीव, दिनांक 25 मार्च 2012 के विज्ञप्ति अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था।

(2) श्रीमती रूचिका जैन जिंदल, भापुसे द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2012 को कर्तव्य पर उपस्थित हो जाने के कारण राज्य शासन द्वारा उनके द्वारा न उपभोग की गई दिनांक 25 फरवरी 2012 से 24 मार्च 2012 तक, कुल तीस दिवस की चार्झल्ड केयर लीव निरस्त की जाती है।

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2012

क्र. एफ-1 (ए) 393-1988-ब-2-दो.—श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, राज्य सायबर पुलिस, पु.मु. भोपाल को

Mid Career Training Programme Phase-V में दिनांक 9 अप्रैल 2012 से 27 अप्रैल 2012 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में एवं दिनांक 30 अप्रैल 2012 से दिनांक 5 मई 2012 तक यू. के. में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 7 से 10 मई 2012 तक, कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India) दिनांक 6 मई 2012 (रविवार) के विज्ञप्ति अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता हैः—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality) स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन पुलिस महानिरीक्षक, राज्य सायबर पुलिस, पु.मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक दास, अपर मुख्य सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2012

क्र. फा. 3(बी)6-2011-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र. 36). राज्य शासन, श्री सुधीर सिंह निगवाल पुत्र श्री गुलाब सिंह निगवाल को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर है। उसकी जन्मतिथि 9 मई, 1987 है।

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2012

क्र. 4-1-2002-इक्कीस-ब(1).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2002 के अनुक्रम में, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर, मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 के अधीन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 मार्च 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्च न्यायिक सेवा के श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (जूनियर) के स्थान पर, श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्डौर को अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर के पद पर, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने अथवा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने (जो भी पहले हो), तक नियुक्त करता है।

उक्त न्यायिक अधिकारी को, देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण, मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा।

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2012

क्र. फा. 3(बी)6-2011-इक्कीस-ब (एक)-शुद्धि-पत्र.—(मेरिट क्र. 36) राज्य शासन, द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26, 30 अप्रैल 2012 की सातवीं पंक्ति में अंकित गृह जिला “ग्वालियर” के स्थान पर “देवास” पढ़ा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2012

फा. क्र. 1(सी)04-2012-एट्रेसिटी-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार शाजापुर जिले के लिये विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4(1) के अनुसार श्री गिरधारीलाल देवतवाल, अधिवक्ता को जिला शाजापुर में विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है।

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी, यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु पैनल अधिवक्ताओं को कार्य चक्रानुक्रम से जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा।

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्यविभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64—मुख्य शीर्ष—2225—(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31—व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां—003— अभिभाषकों को फीस प्रभार के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2012

फा. क्र. 1(बी)-1-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री संतोष कुमार तिवारी पुत्र श्री द्वारका प्रसाद तिवारी, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये टीकमगढ़ सत्र खण्ड के टीकमगढ़ राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, टीकमगढ़ नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

टीप.—श्री संतोष कुमार तिवारी की जन्म तिथि 5-3-1969 पांच मार्च उन्नीस सौ उन्हतर है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 5-3-2031 पांच मार्च दो हजार इक्कीस को पूर्ण होगी।

फा. क्र. 1(बी)-1-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री रतन सिंह ठाकुर पुत्र श्री जगपाल सिंह ठाकुर, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये टीकमगढ़ सत्र खण्ड के टीकमगढ़ राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, टीकमगढ़ नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

टीप.—श्री रतन सिंह की जन्म तिथि 7-6-1975 सात जून उन्नीस सौ पचहतर है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 7-6-2037 सात जून दो हजार सेंतीस को पूर्ण होगी।

फा. क्र. 1(बी)-1-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा, श्री प्रकाश राव पंवार पुत्र श्री आनन्दराव पंवार, अधिवक्ता

को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये रत्नाम सत्र खण्ड के रत्नाम राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, रत्नाम नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

टीप.—श्री प्रकाश राव पंवार की जन्म तिथि 22-4-1973 बाईस अप्रैल उन्नीस सौ तेहतर है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 22-4-2035 बाईस अप्रैल दो हजार पैंतीस को पूर्ण होगी।

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2012

फा. क्र. 1(बी)-9-2004-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 नवम्बर 2004 श्री डी. सिंह, अति. शास. अभिभाषक / अति. लोक अभियोजक, बैतूल को नियुक्त किया गया था।

श्री डी. सिंह, अति. शास. अभिभाषक / अति. लोक अभियोजक की आयु 62 वर्ष की पूर्ण हो जाने से विधि विभाग नियमावली, 2008 के नियम 20 के प्रावधानों के अंतर्गत उनके पद की कालावधि अवसान के आधार पर उक्त पद पर उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2012

फा. क्र. 1(सी)-13-2005-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार रीवा जिले के लिये विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4(1) के अनुसार श्री कुंवर बहादुर सिंह, अधिवक्ता को जिला रीवा में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी, यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु पैनल अधिवक्ताओं को कार्यचक्रानुक्रम से जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा।

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्यविभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64—मुख्य शीर्ष—2225—(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-

31—व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां—003— अभिभाषकों को फीस प्रभार के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

फा. क्र. 1(बी)-30-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा, श्री जयलाल साकेत पुत्र श्री सूर्यदीन साकेत, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये रीवा सत्र खण्ड के रीवा राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, मऊंज नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

टीप.—श्री जयलाल साकेत की जन्म तिथि 1-9-1968 एक सितम्बर उन्नीस सौ अड़सठ है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 1-9-2030 एक सितम्बर दो हजार तीस को पूर्ण होगी।

फा. क्र. 1(बी)-21-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री देवाशीष झा पुत्र श्री देवेन्द्र झा, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मण्डला सत्र खण्ड के मण्डला राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, मण्डला नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

टीप.—श्री देवाशीष झा की जन्म तिथि 1-1-1973 एक जनवरी उन्नीस सौ तेहतर है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 1-1-2035 एक जनवरी दो हजार पैंतीस को पूर्ण होगी।

फा. क्र. 1(बी)-11-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्रीमती आशा किरण कौर पति श्री सुरेन्द्रजीत सिंह, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये गुना सत्र खण्ड के गुना राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, गुना नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

टीप.—श्रीमती आशा किरण कौर की जन्म तिथि 29-5-1965 उन्नीस मई उन्नीस सौ पैंसठ है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि

दिनांक 29-5-2027 उन्नीस मई दो हजार सत्ताईस को पूर्ण होगी।

फा. क्र. 1(बी)-11-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री देवेन्द्र कुमार पलिया पुत्र श्री कहैयालाल जी पलिया, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये गुना सत्र खण्ड के गुना राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, गुना नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

टीप.—श्री देवेन्द्र कुमार पलिया की जन्म तिथि 10-6-1966 दस जून उन्नीस सौ छियासठ है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 10-6-2028 दस जून दो हजार अट्ठाईस को पूर्ण होगी।

फा. क्र. 1(सी)-04-2012-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र जाधव, अधिवक्ता को जिला श्योपुर (म.प्र.) में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी, बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64—मुख्य शीर्ष—2225—(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना—31—व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां—003— अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

भोपाल, दिनांक 1 मई 2012

फा. क्र. 17(ई)-288-2005-इक्कीस-ब(दो).—दिनांक 25 अक्टूबर 2005 द्वारा श्री हितेश कुमार तिवारी, अधिवक्ता / नोटरी, निवासी सूरजगंज, शंकर मंदिर के पास, इटारसी, जिला होशंगाबाद,

मध्यप्रदेश को तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण, तहसील इटारसी में उनका नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन सूची से विलोपित किया जाता है।

**फा. क्र. 17(ई)-284-2005-इक्कीस-ब(दो).**—दिनांक 19 अक्टूबर 2002 द्वारा श्री स्वतंत्र कुमार जैन, अधिवक्ता / नोटरी, निवासी तीसरी लाईन, इटारसी, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश को तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण, तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद में उनका नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन सूची से विलोपित किया जाता है।

**फा. क्र. 17(ई)-256-2006-इक्कीस-ब(दो).**—दिनांक 6 अक्टूबर 2005 द्वारा श्रीमती कल्पना सक्सेना, अधिवक्ता / नोटरी, निवासी जनसेवा रूग्णालय के पास, इटारसी, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश को तहसील इटारसी एवं जिला मुख्यालय होशंगाबाद में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण, तहसील इटारसी एवं जिला मुख्यालय होशंगाबाद में उनका नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन सूची से विलोपित किया जाता है।

**फा. क्र. 1(बी)-32-2004-इक्कीस-ब (दो).**—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा, श्री बद्रीविशाल गुप्ता पुत्र श्री बी. एल. गुप्ता, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये रायसेन सत्र खण्ड के रायसेन राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, बेगमगंज नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

**टीप.**—श्री बद्रीविशाल गुप्ता की जन्म तिथि 27-6-1961 सत्ताईस जून उन्नीस सौ इक्सठ है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 27-6-2023 सत्ताईस जून दो हजार तेर्वेस को पूर्ण होगी।

भोपाल, दिनांक 2 मई 2012

**फा. क्र. 1(बी)-8-2004-इक्कीस-ब (दो).**—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा

(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा, श्री लक्ष्मीनारायण द्विवेदी पुत्र श्री सीताराम द्विवेदी, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये पन्ना सत्र खण्ड के पन्ना राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

**टीप.**—श्री लक्ष्मीनारायण द्विवेदी की जन्म तिथि 15-9-1964 पन्द्रह सितम्बर उन्नीस सौ चौसठ है और उनकी आयु 62 वर्ष की अवधि दिनांक 15-9-2026 पन्द्रह सितम्बर दो हजार छब्बीस को पूर्ण होगी।

**फा. क्र. 1(बी)-22-2004-इक्कीस-ब (दो).**—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा

(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा, श्री दिनेश शर्मा पुत्र स्व. श्री सुन्दरलाल जी शर्मा, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये राजगढ़ सत्र खण्ड के राजगढ़ राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, नरसिंहगढ़ नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

**टीप.**—श्री दिनेश शर्मा की जन्म तिथि 24-4-1968 चौबीस अप्रैल उन्नीस सौ अड़सठ है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 24-4-2030 चौबीस अप्रैल दो हजार तीस को पूर्ण होगी।

**फा. क्र. 1(बी)-22-2004-इक्कीस-ब (दो).**—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा

(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा, श्री गजेन्द्र सिंह पंवार पुत्र श्री रामसिंह पंवार, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये राजगढ़ सत्र खण्ड के राजगढ़ राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, राजगढ़ नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

**टीप.**—श्री गजेन्द्र सिंह पंवार की जन्म तिथि 4-6-1953 चार जून उन्नीस सौ त्रिपन है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 4-6-2015 चार जून दो हजार पन्द्रह को पूर्ण होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनिल वर्मा, सचिव,

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2012

फा. क्र. 17(ई)83-03-3056-इकीस-ब (एक)-011-1235-12.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17(ई)83-03-इकीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 6, 17, 18, 23, 44, 55, 57, 63, 64, 66, 68, 71, 74, 92, 101 एवं 108 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

### सारणी

क्र.	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
06	बालाघाट	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट	सिविल जिला बालाघाट का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 7 में यथाविनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
17	बुरहानपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) बुरहानपुर.	सिविल जिला बुरहानपुर का समस्त विद्युत क्षेत्र.
18	छतरपुर	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर	सिविल जिला छतरपुर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 19 तथा 20 में यथाविनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
23	दमोह	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह	सिविल जिला दमोह का समस्त विद्युत क्षेत्र.
44	होशंगाबाद	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), पिपरिया.	पिपरिया का समस्त विद्युत क्षेत्र.
55	मण्डला	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डला	सिविल जिला मण्डला का समस्त विद्युत क्षेत्र.
57	मन्दसौर	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मन्दसौर	सीतामऊ का विद्युत क्षेत्र (राजस्व तहसील सीतामऊ एवं सुवसरा को सम्मिलित कर).
63	मुरैना	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जौरा	जौरा का विद्युत क्षेत्र.
64	नरसिंहपुर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहपुर	सिविल जिला नरसिंहपुर के समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 65 में यथाविनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
66	नीमच	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नीमच	सिविल जिला नीमच के समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 67 में यथाविनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
68	पन्ना	विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां / अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, पन्ना.	सिविल जिला पन्ना के समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 69 में यथाविनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).

(1)	(2)	(3)	(4)
71	रायसेन	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट), बेगमगंज.	बेगमगंज का विद्युत क्षेत्र.
74	राजगढ़	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), नरसिंहगढ़.	नरसिंहगढ़ का विद्युत क्षेत्र.
92	शहडोल	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट), ब्यौहारी.	ब्यौहारी का विद्युत क्षेत्र.
101	सीधी	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सीधी	सिविल जिला सीधी के समस्त विद्युत क्षेत्र (अनु-क्रमांक 102 में यथाविनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
108	विदिशा	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय का प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), बासौदा.	बासौदा का विद्युत क्षेत्र

टिप्पणी.—विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे।

F. No. 17(E)83-03-3056-XXI-B(1)-011-1235-12.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 OF 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette dated 24th September, 2010 namely:—

#### AMENDMENT

In the said notification, in the table for serial numbers 6, 17, 18, 23, 44, 55, 57, 63, 64, 66, 68, 71, 74, 92, 101 and 108 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

#### TABLE

No.	Name of Civil District (1)	Name of Special Court (2)	Territorial jurisdiction of the Special Court (According to Electricity Area) (4)
6	Balaghat	IInd ASJ, Balaghat	All Electricity area of Civil District Balaghat (excluding the jurisdiction of Special Court as specified at serial No. 7).
17	Burhanpur	AJ to the Court of ASJ (FTC) Burhanpur.	All Electricity area of Civil District Burhanpur.
18	Chhatarpur	IVth ASJ, Chhatarpur	All Electricity area of Civil District Chhatarpur (excluding the jurisdiction of Special Court as specified at serial No. 19 & 20).
23	Damoh	IIIrd ASJ, Damoh	All Electricity area of Civil District Damoh.
44	Hoshangabad	ASJ (FTC), Piparia	All Electricity area of Piparia.

(1)	(2)	(3)	(4)
55	Mandla	Ist ASJ, Mandla	All Electricity area of Civil District Mandla.
57	Mandsaur	IIInd ASJ, Mandsaur	Electricity area of Sitamau (including the territorial limits of Sitamow & Suvasara).
63	Morena	IIInd ASJ, Jora	Electricity area of Jora
64	Narsinghpur	Ist ASJ, Narsinghpur	All Electricity area of Civil District Narsinghpur (excluding the jurisdiction of Special Court as specified at serial No. 65).
66	Neemuch	Ist ASJ, Neemuch	All Electricity area of Civil District Neemuch (excluding the jurisdiction of Special Court as specified at serial No. 67).
68	Panna	Special Judge SC/ST (POA) Act, Panna.	All Electricity area of Civil District Panna (excluding the jurisdiction of Special Court as specified at serial No. 69).
71	Raisen	IIInd ASJ (FTC) Begumganj	Electricity area of Begumganj.
74	Rajgarh	AJ to the Court of ASJ (FTC) Narsinghgarh.	Electricity area of Narsinghgarh.
92	Shahdol	ASJ (FTC) Beohari	Electricity area of Beohari.
101	Sidhi	Ist ASJ, Sidhi	All Electricity area of Civil District Sidhi (excluding the jurisdiction of Special Court as specified at serial No. 102).
108	Vidisha	Ist AJ to IIInd ASJ (FTC) Basoda.	Electricity area of Basoda.

**Note.—**The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to newly constituted court according to their territorial jurisdiction.

फा. क्र. 17(ई)83-03-3056-इक्कीस-ब (एक)-011-1235-12.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का संख्याक 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 6, 8, 12, 17, 18, 22, 23, 26, 33, 36, 39, 42, 44, 48, 55, 57, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 74, 76, 83, 84-ए, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 97, 100, 101, 104, 108 एवं 112 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

### सारणी

क्र.	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
06	बालाघाट	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट.

(1)	(2)	(3)	(4)
08	बड़वानी	विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां/अनु-सूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बड़वानी.	श्री डी. एस. सोलंकी, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बड़वानी.
12	भिण्ड	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड	श्री आर. सी. वार्ष्णेय, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड.
17	बुरहानपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) बुरहानपुर.	कु. सुनीता सिरिल बारलो, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) बुरहानपुर.
18	छतरपुर	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर	श्री कृष्ण मूर्ति मिश्रा, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर.
22	छिन्दवाड़ा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), अमरवाड़ा.	श्री किसना अतुलकर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), अमरवाड़ा.
23	दमोह	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह	श्री महेश चन्द्र सोनी, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह.
26	देवास	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवास	श्री राजेश कुमार गुप्ता, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवास.
33	डिंडोरी	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डिंडोरी	श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डिंडोरी.
36	गुना	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना	श्री सुरेश कुमार चौबे (सीनि.), तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना.
39	ग्वालियर	*अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 4, ग्वालियर.	श्री राकेश कुमार गुप्ता, *अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 4, ग्वालियर.
42	होशंगाबाद	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, होशंगाबाद	श्री योगेश दत्त (शुक्ला), प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, होशंगाबाद.
44	होशंगाबाद	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), पिपरिया.	श्री काशीनाथ सिंह, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), पिपरिया.
48	इन्दौर	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर	श्री भरत सिंह ओहरिया, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर.
55	मण्डला	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डला	श्री राजीव कुमार कर्महे, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डला.
57	मन्दसौर	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मन्दसौर	श्री सुनील कुमार जैन (सीनि.) तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मन्दसौर.
60	मुरैना	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुरैना	श्री राकेश श्रोती, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुरैना.
62	मुरैना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सबलगढ़	श्री विवेक कुमार गुप्ता, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सबलगढ़.

(1)	(2)	(3)	(4)
63	मुरैना	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जौरा	श्री मधुसूदन मिश्रा, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जौरा.
64	नरसिंहपुर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहपुर	श्री अजय कुमार गर्ग, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहपुर.
66	नीमच	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नीमच	श्रीमती विधि सक्सेना, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नीमच.
68	पन्ना	विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां / अनु-सूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, पन्ना.	श्री बी. के. निगम, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां / अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, पन्ना.
70	रायसेन	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रायसेन	श्री शिवचरण पांडे, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रायसेन.
71	रायसेन	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट), बेगमगंज.	श्री कमल जोशी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट), बेगमगंज.
74	राजगढ़	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट), के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, नरसिंहगढ़.	श्री भैयालाल वर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट), के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, नरसिंहगढ़.
76	रतलाम	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावरा	श्री ए. के. वर्मा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावरा.
83	सतना	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना	श्री उमेश चन्द्र मिश्रा, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना.
84-क	सतना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नागौद	श्री वाचस्पति मिश्र, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नागौद.
87	सीहोर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट), आष्टा.	श्री सत्येन्द्र गोवर्धनलाल जोशी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट), आष्टा.
88	सीहोर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नसरूल्लालगंज.	श्री शशिभूषण पाठक, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नसरूल्लालगंज.
89	सिवनी	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट), सिवनी.	श्रीमती ललिता धुर्वे, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट), सिवनी.
92	शहडोल	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट), ब्यौहारी.	कु. निर्मला चावड़ा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट), ब्यौहारी.
93	शाजापुर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शाजापुर	कु. साधना माहेश्वरी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शाजापुर.
94	शाजापुर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट), शुजालपुर.	श्रीमती माया विश्वलाल, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट), शुजालपुर.
97	श्योपुर	विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां / अनु-सूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, श्योपुर.	श्री शिशिरकांत चौबे, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जातियां / अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, श्योपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)
100	शिवपुरी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिछोर	श्री सुबोध कुमार जैन, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिछोर.
101	सीधी	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सीधी	श्री अखिलेश चंद्र शुक्ला, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सीधी.
104	उज्जैन	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन	श्री राजेन्द्र कुमार वाणी, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन.
108	विदिशा	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश बासौदा.	श्री पी. सी. आर्य, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, बासौदा.
112	प.नि. मण्डलेश्वर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़वाह	श्री जसवीर कौर सासन, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़वाह.

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1)-1235-12.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153(2) of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following Amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I dated 24th September, 2010 namely:—

#### AMENDMENT

In the said notification, in the table for serial numbers 6, 8, 12, 17, 18, 22, 23, 26, 33, 36, 39, 42, 44, 48, 55, 57, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 74, 76, 83, 84-A, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 97, 100, 101, 104, 108 and 112 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

#### TABLE

S.No,	Name of Civil District (1)	Name of Special Court (2)	Name of the Judge of the Special Court (4)
06	Balaghat	IInd ASJ, Balaghat	Shri Rajendra Prasad Gupta, IInd ASJ, Balaghat
08	Barwani	Special Judge SC/ST (POA) Act, Barwani.	Shri D. S. Solanki, Special Judge SC/ST (POA) Act, Barwani.
12	Bhind	Ist ASJ, Bhind	Shri R. C. Varshney, Ist ASJ, Bhind
17	Burhanpur	AJ to the Court of ASJ (FTC) Burhanpur.	Ku. Sunita Ciril Barlow, AJ to the Court of ASJ (FTC) Burhanpur.
18	Chhatarpur	IVth ASJ, Chhatarpur	Shri Krishna Murty Mishra, IVth ASJ, Chhatarpur.
22	Chhindwara	ASJ (FTC), Amarwara	Shri Kisna Atulkar, ASJ (FTC), Amarwara.
23	Damoh	IIInd ASJ, Damoh	Shri Mahesh Chandra Soni, IIInd ASJ, Damoh.
26	Dewas	IVth ASJ, Dewas	Shri Rajesh Kumar Gupta, IVth ASJ, Dewas.

(1)	(2)	(3)	(4)
33	Dindori	District & Session Judge, Dindori	Smt. Anjuli Palo, District & Session Judge, Dindori.
36	Guna	IIIrd ASJ, Guna	Shri Suresh Kumar Choubey (Sr.), IIIrd ASJ, Guna.
39	Gwalior	ASJ, Spl. Court No. 4, Gwalior	Shri Rakesh Kumar Gupta, ASJ, Spl. Court No. 4, Gwalior
42	Hoshangabad	Ist ASJ, Hoshangabad	Shri Yogesh Dutta (Shukla), Ist ASJ, Hoshangabad.
44	Hoshangabad	ASJ (FTC), Piparia	Shri Kashinath Singh, ASJ (FTC), Piparia.
48	Indore	IIIrd ASJ, Indore	Shri Bharat Singh Ohriya, IIIrd ASJ, Indore.
55	Mandla	Ist ASJ, Mandla	Shri Rajeev Kumar Karmahe, Ist ASJ, Mandla.
57	Mandsaur	IIIrd ASJ, Mandsaur	Shri Sunil Kumar Jain, IIIrd ASJ, Mandsaur.
60	Morena	IIInd ASJ, Morena	Shri Rakesh Kumar Shotriya, IIInd ASJ, Morena.
62	Morena	ASJ, Sabalgarh	Shri Vivek Kumar Gupta, ASJ, Sabalgarh.
63	Morena	IIInd ASJ, Jora	Shri Madhu Sudan Mishra, IIInd ASJ, Jora.
64	Narsinghpur	Ist ASJ, Narsinghpur	Shri Ajay Kumar Garg, Ist ASJ, Narsinghpur.
66	Neemuch	Ist ASJ, Neemuch	Smt. Vidhi Saxena, Ist ASJ, Neemuch.
68	Panna	Special Judge SC/ST (POA) Act, Panna.	Shri B. K. Nigam, Special Judge SC/ST (POA) Act, Panna.
70	Raisen	IIInd ASJ, Raisen	Shri Shiv Charan Pandey, IIInd ASJ, Raisen.
71	Raisen	IIInd ASJ (FTC) Begumganj	Shri Kamal Joshi, IIInd ASJ (FTC) Begumganj.
74	Rajgarh	AJ to the Court of ASJ (FTC) Narsinghgarh.	Shri Bhaihalal Verma, AJ to the Court of ASJ (FTC), Narsinghgarh.
76	Ratlam	Ist ASJ, Jaora	Shri A. K. Verma, Ist ASJ, Jaora.
83	Satna	IIIrd ASJ, Satna	Shri Umesh Chandra Mishra, IIIrd ASJ, Satna.
84-A	Satna	ASJ, Nagod	Shri Vachspati Mishra, ASJ, Nagod.
87	Sehore	IIInd ASJ, (FTC) Astha	Shri Satyendra Goverdhanlal Joshi, IIInd ASJ, (FTC) Astha.
88	Sehore	Ist ASJ, Nasrullaganj	Shri Shashi Bhushan Pathak, Ist ASJ, Nasrullaganj.
89	Seoni	IIIrd ASJ (FTC), Seoni	Smt. Lalita Dhurve, IIIrd ASJ (FTC), Seoni.
92	Shahdol	ASJ (FTC) Beohari	Ku. Nirmla Chawda, ASJ (FTC) Beohari.
93	Shajapur	IIInd ASJ, Shajapur	Ku. Sadhna Maheshwari, IIInd ASJ, Shajapur.
94	Shajapur	IIInd ASJ (FTC), Shujalpur	Smt. Maya Vishwalal, IIInd ASJ (FTC), Shujalpur.

(1)	(2)	(3)	(4)
97	Sheopur	Special Judge SC/ST (POA) Act, Sheopur.	Shri Shishir Kant Choubey, Special Judge SC/ST (POA) Act, Sheopur.
100	Shivpuri	ASJ, Pichore	Shri Subhodh Kumar Jain, ASJ, Pichore
101	Sidhi	Ist ASJ, Sidhi	Shri Akhilesh Chandra Shukla, Ist ASJ, Sidhi.
104	Ujjain	IVth ASJ, Ujjain	Shri Rajendra Kumar Vani, IVth ASJ, Ujjain
108	Vidisha	Ist AJ to IIInd ASJ (FTC) Basoda.	Shri P. C. Arya, Ist AJ to IIInd ASJ (FTC) Basoda.
112	W.N. Mandleshwar.	ASJ, Barwah	Ku. Jasweer Kaur Sasan, ASJ, Barwah.

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक).—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 7 नवम्बर, 2009 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक, दिनांक 20 नवम्बर, 2009 को प्रकाशित हुई थी, को आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, श्री संजीव कुमार सरेया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का सं. 25) के अधीन, अन्वेषण किये गये मामलों के विचारण के लिये, नीचे विनिर्दिष्ट किये गये राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है, जिनका मुख्यालय भोपाल होगा, अर्थात् :—

### राजस्व जिले

1. ग्वालियर, 2. गुना, 3. शिवपुरी, 4. छतरपुर, 5. दतिया, 6. अशोकनगर, 7. भिणड.

F. No. 1-5-96-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) and in partial supersession of this Department's Notification No. F. No. 1-5-96-XXI-B(1), dated 7th November 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I, dated 20th November 2009, the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints Shri Sanjeev Kumar Sariya, Additional Sessions Judge, Bhopal, as Special Judge with Headquarter at Bhopal, for the area comprising of the Revenue District specified below to try the cases in regard to the offences specified in Clauses (a) & (b) of sub-section (1) of Section 3 of the said Act, investigated under Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) by Delhi Police and Central Bureau of Investigation, namely :—

### Revenue District

1. Gwalior, 2. Guna, 3. Shivpuri, 4. Chhattarpur, 5. Datia, 6. Ashoknagar, 7. Bhind.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

**आवास एवं पर्यावरण विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2012

क्र. एफ-3-81-बत्तीस-2012.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (संशोधन 1996) की धारा 17-क (1) के अन्तर्गत पूर्व में खण्डवा विकास योजना हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ-3-19-बत्तीस-99, दिनांक 19 जनवरी 1999 के द्वारा समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति को निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है। यह समिति अधिनियम की धारा 17-क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :—

अधिनियम की धारा 17 क(1)की उपधारा	पद/व्यक्ति का नाम	संस्था का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	महापौर	नगरपालिक निगम, खण्डवा	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, खण्डवा	सदस्य
(ग)	सांसद	लोक सभा क्षेत्र, खण्डवा	सदस्य
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र, खण्डवा	सदस्य
(ङ)	लागू नहीं.	लागू नहीं।	—
(च)	1. अध्यक्ष 2. अध्यक्ष	जनपद पंचायत, छैगांव माखन	सदस्य
(छ)	1. सरपंच 2. सरपंच 3. सरपंच 4. सरपंच 5. सरपंच	ग्राम पंचायत, नागचून (नागचून, मालीपुरा) ग्राम पंचायत, बोरगांव खुर्द (बोरगांव खुर्द, नांदुखेड़ी) ग्राम पंचायत, नहालदा (नहालदा, भंडारिया) ग्राम पंचायत, छैगांवदेवी (छैगांवदेवी) ग्राम पंचायत, सुलगांव जोशी (धोडखेड़ी, महताखेड़ी, रानियाखेड़ी)	सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
	6. सरपंच 7. सरपंच 8. सरपंच	ग्राम पंचायत, रहमापुर (रहमापुर) ग्राम पंचायत, रोशनाई (रोशनाई) ग्राम पंचायत, बड़गांवभिला (बड़गांवभिला)	सदस्य सदस्य सदस्य
(ज)	प्रतिनिधि प्रतिनिधि प्रतिनिधि प्रतिनिधि प्रतिनिधि प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला खण्डवा इंस्टीट्यूट ऑफ टाइन प्लानर्स इंडिया काउंसिल ऑफ आर्टिक्वर ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया आयुक्त, नगरपालिक निगम, खण्डवा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, खण्डवा	सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
(झ)	प्रतिनिधि समिति का संयोजक	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्डवा उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, खण्डवा	सदस्य समिति संयोजक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 वर्षा नावलेकर, उपसचिव,

## विभाग प्रमुखों के आदेश

### मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2012

**क्र. सह.अधि.-रीडर-2012.—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम क्रमांक-3 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के संभागीय मुख्यालय, जबलपुर में माननीय अध्यक्ष श्री के. सी. शर्मा एवं माननीय सदस्य श्री जी. सी. केवलरामानी, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल द्वारा प्रकरणों की सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 18 मई 2012 को नियत की गई है। इस दिवस को पेशी स्थान कार्यालय, कमिशनर जबलपुर, राजस्व संभाग, जबलपुर में समय सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच होगी। एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित करें।**

**माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,  
विमल श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार**

### मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

**“निर्वाचन भवन”**

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश 462 011

### आदेश

भोपाल, दिनांक 3 मई 2012

**क्र. एफ. 67-70-10-तीन-689.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।**

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित

अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद, शुजालपुर, जिला शाजापुर के आम निर्वाचन में श्रीमती दूर्गा पाटीदार, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं। इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, श्रीमती दूर्गा पाटीदार को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, शाजापुर के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शाजापुर के पत्र दिनांक 24 जुलाई 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती दूर्गा पाटीदार द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती दूर्गा पाटीदार को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 18 अगस्त 2010 जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शाजापुर के माध्यम से दिनांक 24 सितम्बर 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में श्रीमती दूर्गा पाटीदार से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी श्रीमती दूर्गा पाटीदार को नोटिस दिनांक 14 सितम्बर 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 29 सितम्बर 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शाजापुर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 14 फरवरी 2012 के द्वारा लेख किया है कि प्रतिवेदन दिनांक 14 फरवरी 2012 तक अभ्यर्थी श्रीमती दूर्गा पाटीदार द्वारा जिला कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधी किसी प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 10 अप्रैल 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती दूर्गा पाटीदार आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई। अभ्यर्थी श्रीमती दूर्गा पाटीदार द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया। व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली श्रीमती दूर्गा पाटीदार को दिनांक 31 मार्च 2012 को कराई गई। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती दूर्गा पाटीदार द्वारा

नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती दूर्गा पाटीदार को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पालिका परिषद, शुजालपुर, जिला शाजापुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 3 मई 2012

क्र. एफ. 67-70-10-तीन-690.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्म में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद, शुजालपुर, जिला शाजापुर के आम निर्वाचन में श्रीमती सीमा

सेनी पत्नि श्री महेश सेनी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं। इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, श्रीमती सीमा सेनी पत्नि श्री महेश सेनी को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, शाजापुर के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शाजापुर के पत्र दिनांक 24 जुलाई 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती सीमा सेनी पत्नि श्री महेश सेनी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती सीमा सेनी पत्नि श्री महेश सेनी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 18 अगस्त 2010 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, शाजापुर के माध्यम से दिनांक 6 सितम्बर 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में श्रीमती सीमा सेनी पत्नि श्री महेश सेनी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी श्रीमती सीमा सेनी पत्नि श्री महेश सेनी को नोटिस दिनांक 6 सितम्बर 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 21 सितम्बर 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शाजापुर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 14 फरवरी 2012 के द्वारा लेख किया है कि प्रतिवेदन दिनांक 14 फरवरी 2012 तक अभ्यर्थी श्रीमती सीमा सेनी पत्नि श्री महेश सेनी द्वारा जिला कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधी किसी प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 10 अप्रैल 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, जिसके व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली श्रीमती सीमा सेनी पत्नि श्री महेश सेनी को विहित समयावधि में दिनांक 31 मार्च 2012 को कराई गई। अभ्यर्थी श्रीमती सीमा सेनी पत्नि श्री महेश सेनी उक्त दिवस को आयोग कार्यालय में उपस्थित हुई। अभ्यर्थी श्रीमती सीमा सेनी पत्नि श्री महेश सेनी ने समक्ष में उपस्थित होकर अपना आवेदन एवं व्यय लेखा लगभग 02 वर्ष तीन माह उपरान्त विलम्ब से प्रस्तुत किया गया, जिस पर सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं

है एवं शपथ-पत्र भी रिक्त है. श्रीमती सीमा सेनी द्वारा विहित समयावधि में लेखा प्रस्तुत न करने का कोई ठोस एवं संतोषजनक कारण नहीं बताया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती सीमा सेनी पत्नि श्री महेश सेनी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती सीमा सेनी पत्नि श्री महेश सेनी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद, शुजालपुर, जिला शाजापुर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 03 वर्ष (तीन वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( सुभाष जैन )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 मई 2012

क्र. एफ. 67-86-10-तीन-698.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अध्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामानिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अध्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित

अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद, महिदपुर, जिला उज्जैन के आम निर्वाचन में सुश्री हसीना फिदाहुसैन कुरैशी “पार्षद” अध्यक्ष पद के अध्यर्थी थीं। इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2009 को शासकीय अवकाश होने से दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, सुश्री हसीना फिदाहुसैन कुरैशी “पार्षद” को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, उज्जैन के पास दाखिल करना था, किन्तु क्लेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उज्जैन के पत्र दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री हसीना फिदाहुसैन कुरैशी “पार्षद” द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का अपूर्ण लेखा “निक्षेप राशि की रसीद अप्राप्त” दाखिल किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का अपूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, आयोग द्वारा सुश्री हसीना फिदाहुसैन कुरैशी “पार्षद” जिला स्तर पर व्यय लेखा पूर्ण किये जाने हेतु क्लेक्टर, उज्जैन को दिनांक 27 जनवरी 2010 को पत्र जारी किया गया, जिसके जवाब में उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 25 जून 2010 प्रतिवेदित किया गया है कि सुश्री हसीना फिदाहुसैन कुरैशी को 7 दिवस में व्यय लेखा पूर्ण करने (निक्षेप राशि की रसीद प्रस्तुत करने) हेतु जिला स्तर पर सूचना दी गई थी, जिसकी तामीली दिनांक 22 मार्च 2010 को होने के उपरान्त भी उनके द्वारा प्रतिवेदन दिनांक तक उक्त पूर्णता नहीं की गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उज्जैन से उक्त जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त आयोग द्वारा अध्यर्थी सुश्री हसीना फिदाहुसैन कुरैशी “पार्षद” को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 30 अगस्त 2010 को जारी कर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उज्जैन के माध्यम से दिनांक 21 सितम्बर 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में सुश्री हसीना फिदाहुसैन कुरैशी “पार्षद” से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी सुश्री हसीना फिदाहुसैन कुरैशी “पार्षद” को नोटिस दिनांक 21 सितम्बर 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको नोटिस तामीली उपरान्त दिनांक 6 अक्टूबर 2010 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उज्जैन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 13 अक्टूबर 2011 में अंकित किया गया है कि सुश्री हसीना फिदाहुसैन कुरैशी को आयोग द्वारा जारी नोटिस तामीली कराये जाने के पश्चात् उनके द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 13 अक्टूबर 2011 तक उनके कार्यालय में कोई अभ्यावेदन इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही व्यय लेखे में सुधार हेतु कार्यालय से सम्पर्क किया गया है.

विचारोपरांत अभ्यर्थी सुश्री हसीना फिदाहुसैन कुरैशी को दिनांक 28 दिसम्बर 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में सुश्री हसीना फिदाहुसैन कुरैशी “पार्षद” को दिनांक 25 नवम्बर 2011 को कराई गई. लेकिन अभ्यर्थी सुश्री हसीना फिदाहुसैन कुरैशी “पार्षद” आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई न ही उनके द्वारा इस संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि

सुश्री हसीना फिदाहुसैन कुरैशी “पार्षद” द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा की अपूर्ण जानकारी “निक्षेप राशि की रसीद अप्राप्त” प्रस्तुत की गई है, जिसे पूर्ण नहीं किया गया है. अतः आयोग का समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा की पूर्ण जानकारी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री हसीना फिदाहुसैन कुरैशी “पार्षद” को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर प्रालिका परिषद, महिदपुर, जिला उज्जैन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 03 वर्ष (तीन वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 2 मई 2012

क्र. एफ.-1-3-11-रा.स.-यू.ए-1-649-संशोधित अधिसूचना.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के तहत इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ.-1-3-11-रा.स.-यू.ए-1-413, दिनांक 22 मार्च 2012 के द्वारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिये तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था. उक्त समिति में प्रो. एस. सुदर्शन शर्मा (महामहिम कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित एवं समिति के अध्यक्ष), प्रो. आर. आर. शर्मा (अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित) एवं डॉ. आई. वी. त्रिवेदी (देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की कार्यपरिषद द्वारा निर्वाचित) सदस्य शामिल थे. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित सदस्य प्रो. आर. आर. शर्मा के द्वारा समिति की बैठक हेतु समय प्रदान नहीं करने के कारण समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी है. परिणामस्वरूप छः सप्ताह की निर्धारित समयावधि में समिति से कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल प्राप्त नहीं हो सका है.

2. अतः, प्रो. आर. आर. शर्मा के स्थान पर अन्य महानुभाव को समिति में सदस्य नामांकित करने हेतु अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया गया था. तदनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ. 13-1/2011 (सी.पी.पी. II) दिनांक 1 मई 2012 के परिप्रेक्ष्य में प्रो. आर. आर. शर्मा के स्थान पर प्रो. एच. पी. दीक्षित, डी-10/1, चार इमली, भोपाल को उक्त समिति में सदस्य नामांकित किया जाता है. समिति में नामांकित अन्य सदस्य यथावत् समिति के सदस्य रहेंगे.

3. चूंकि, समिति के द्वारा पूर्व निर्धारित समयावधि में पैनल प्रस्तुत नहीं किया गया है. अतः मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा (5) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम कुलाधिपतिजी के द्वारा समिति को पूर्व निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में 2 सप्ताह की वृद्धि की गई है.

कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के आदेशानुसार,

जे. एन. मालपानी, राज्यपाल के सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 2 मई 2012

क्र. एस. डब्ल्यू.-14-15-09-12-4381.—मध्यप्रदेश शासन, गृह पुलिस विभाग के आदेश क्र. एफ-2(क)-9-08-बी-3-2, दिनांक 30 जुलाई, 2010 के द्वारा जिले के भीतर स्वीकृत थाने की सीमा के निर्धारण का अधिकार जिला स्तर पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की समिति को प्रत्यायोजित किये गये हैं। उक्तानुसार जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रयोग करते हुये थाना क्षेत्र हजीरा एवं ग्वालियर की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया है। जिसके अंतर्गत थाना क्षेत्र हजीरा के निम्नलिखित मोहल्ले/ग्राम थाना ग्वालियर क्षेत्र में सम्मिलित किये गये हैं, शेष क्षेत्र यथावत् रहेगा:—

पुलिस थाने का नाम (तहसील व जिला) जिसे अपवर्जित किया गया	ग्राम/मोहल्ला का नाम व वार्ड / बन्दोबस्त क्रमांक (2)	ग्राम/मोहल्ले का नाम गोसपुरा नं. 1 (रानीपुरा सहित) गोसपुरा नं. 2 (तानसेन नगर, स्टेट बैंक चौकी से हजीरा की तरफ जाने वाले रास्ते के बांयी ओर का भाग सहित).	पुलिस थाने का नाम जिसमें सम्मिलित किया गया
(1)	(3)	(4)	
हजीरा		वार्ड/बन्दोबस्त क्र. 11/80, 09 (आंशिक)/304	ग्वालियर
		11 (आंशिक), 13/80	

**नोट।—**स्टेशन से हजीरा की ओर जाने वाले तानसेन रोड के बांयी ओर का भाग थाना ग्वालियर में तथा दाहिने ओर का भाग थाना हजीरा में शामिल होगा। हजीरा से होकर चार शहर का नाका और चार शहर का नाका से सागर ताल की ओर जाने वाले रोड के बांयी ओर का भाग ग्वालियर में तथा दाहिने ओर का भाग थाना हजीरा में शामिल होगा।

Name of Police Station and District from which excluded (1)	Local area name of village and settlement/Halka No. (2)	Ward No./Survey No. (3)	Name of Police station with Tehsil and District in which included (4)
Police Station Hazira Tahsil Gwalior District Gwalior.	Goshpura No. 1 (Including Ranipura)	11/80, 09 (Partial)/304	Police Station Gwalior Tahsil Gwalior District Gwalior
	Goshpura No. 2 (Including Tansen Nagar, Left Side of the road from State Bank Chowki to Hazira)	11 (Partial)/13/80	

**Note.—**The left side of the road of station to Hazira will be included in the Police Station Gwalior and the right side in the Police Station Hazira. Similarly, the left side of the road from Hazira to Char Shahar Ka Naka and towards Sagartal will be included in the Police Station Gwalior and right side in Police Station Hazira.

पी. नरहरि, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी।

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 26 मई 2010

**क्र. 506-भू-अर्जन-2010.**—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	1. उमरीमाधौ 2. उमरी श्रीपति 3. उमरी श्रीपति 4. निविहा 5. उमरी मुसलमान	0.380 1.166 2.777 0.944 0.096	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, रीवा संभाग, रीवा।	बेलहा जलाशय योजना नहर निर्माण।
		योग . .	<u>5.363</u>		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है बेलहा जलाशय योजना नहर निर्माण।  
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर महोदय के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,**

**कार्यालय, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,**  
**राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 25 अप्रैल 2012

**क्र. 904-भू-अर्जन-2012.**—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है

कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्रमांक 1, रीवा (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि पर एफ.आर.एल. एवं एम.डब्ल्यू.एल. के मध्य स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 28 अप्रैल 2012

क्र. 942-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित इस धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्रमांक 2, सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के निर्माण के अन्तर्गत महिदलकला वितरक नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, चिरहुला कालोनी रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 940-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध

उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
सतना	कोटर	मझियार	निजी भूमि 0.359	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्रमांक 2, सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के निर्माण के अन्तर्गत महिदलकला वितरक नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.	

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, चिरहुला कालोनी, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 944-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
सतना	कोटर	गाजन कोठार	निजी भूमि 0.426	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्रमांक 2, सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के निर्माण के अन्तर्गत महिदलकला वितरक नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.	

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, चिरहुला कालोनी, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 946-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है

कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	देवमऊदलादल	निजी भूमि 0.380	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्रमांक 2, सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के निर्माण के अन्तर्गत महिदलकला वितरक नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, चिरहुला कालोनी रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 948-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	महिदलखुर्द	निजी भूमि 0.333	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्रमांक 2, सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के निर्माण के अन्तर्गत महिदलकला वितरक नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, चिरहुला कालोनी रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 950-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है

कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	बेला कोठार	निजी भूमि 0.294	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग, क्रमांक 2, सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के निर्माण के अन्तर्गत महिदलकला वितरक नहर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, चिरहुला कालोनी, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 952-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	करहिया	0.097	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).	शिकारांज वितरक नहर क्र. 2 के अन्तर्गत 0.097 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 4 मई 2012

क्र. 1018-प्रशा.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है

कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान.	तपा	10.56	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर, पुरवा नहर संभाग, क्रमांक 2, सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि- अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1020-प्रशा.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान.	महुरछ	1.32	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2, सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि- अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1022-प्रशा.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान.	सेल्हना पैप खार.	1.166	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2, सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि- अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1024-प्रशा.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान.	टिकुरी कोठार.	1.144	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2, सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि- अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1026-प्रशा.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान.	बढ़ौरा कोठार	1.276	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक 2, सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि- अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव,

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्र. 280-भू-अर्जन-1-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	सिराली	कडोलाराघौ	0.405	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	ईमलीढाना जलाशय निर्माण हेतु पूरक प्रस्ताव.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुदाम खांडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 17 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 01-अ-82-2011-12-211.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग रकबा (हैक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के डूब प्रभावितों हेतु ग्राम डाबर से पोखरबुजुर्ग पहुंच मार्ग में आने के कारण.
देवास	सतवास	पोखरबुजुर्ग	कुषि भूमि रकबा 1.408		

नोट.—भूमि का नक्शा व प्लान आदि (1) कार्यालय कलेक्टर जिला देवास, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 खण्डवा, मध्यप्रदेश (3) कार्यालय भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एन. एच. डी. सी. खण्डवा क्र. 4 में देखा जा सकता है।

क्र. 03-अ-82-2011-12-217.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2)के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	टोंकखुर्द	बालोन	0.37	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन देवास.	चांदगढ़ तालाब नहर में आने वाली भूमि.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला देवास कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी सोनकछु में देखा जा सकता है।

देवास, दिनांक 18 अप्रैल 2012

क्र. 238-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 02-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2)के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	देवास	हीरली	20.969	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उज्जैन.	सेवरखेड़ी मध्यम जलाशय योजनान्तर्गत निर्माण में आने वाली निजी भूमि के अर्जन बाबत्.

नोट.—भूमि के नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला देवास एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उज्जैन में देखा जा सकता है।

क्र. 232-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 03-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2)के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	देवास	अंतरालिया	5.421	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उज्जैन.	सेवरखेड़ी मध्यम जलाशय योजनान्तर्गत निर्माण में आने वाली निजी भूमि के अर्जन बाबत्.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला देवास एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उज्जैन में देखा जा सकता है।

क्र. 226-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 04-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	देवास	देवर	8.882	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उज्जैन.	सेवरखेड़ी मध्यम जलाशय योजनान्तर्गत निर्माण में आने वाली निजी भूमि के अर्जन बाबत,

नोट.—भूमि के नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर, जिला देवास एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उज्जैन में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुकेशचन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2012

क्र. 374-भू-अर्जन-रीडर-1-2012-प्र.क्र. 22-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	अलीराजपुर	रिछवी	0.49	डिप्टी चीफ इन्जीनियर (निर्माण) बेस्टर्न रेलवे, (बडौदा).	छोटा उदयपुर-धार हेतु रेलवे लाईन

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 377-भू-अर्जन-रीडर-1-2012-प्र.क्र. 21-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	अलीराजपुर	गड़ात	14.68	डिस्ट्री चीफ इन्जीनियर (निर्माण) वेस्टर्न रेलवे, (बड़ौदा)	छोटा उदयपुर-धार हेतु रेलवे लाईन

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 23 अप्रैल 2012

क्र. 1003-भू-अर्जन-2012-प्र.क्र. 02-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मन्दसौर	दलौदा	चौसला	0.10	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर।	चौसला तालाब के ढूब में आने वाले रस्ते हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड मन्दसौर के यहां देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 27 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 17-अ-82-11-12-1159.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				(1)	(2)	(3)
विदिशा	कुरवाई	मनेशा	0.564	भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई		रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध के डूब क्षेत्र हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 18-अ-82-11-12-1161.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				(1)	(2)	(3)
विदिशा	कुरवाई	परसौरा	1.336	भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई		रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध के डूब क्षेत्र हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 30 अप्रैल 2012

क्र. 53-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(4)		
(1)	(2)	(3)			(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	करहिया	21.087	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग डबरा,	हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु,	
		योग . .	<u>21.087</u>		जिला ग्वालियर.	

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

डिण्डौरी, दिनांक 30 अप्रैल 2012

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)-2011-12-286-ए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपर्योग के अनुसार संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुका	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ ग्राम	सर्वे नम्बर		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	मोरचा ऐ. प. ह. नं. 5	निजी भूमि 203	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	टिकिरिया (सिलहरी) जलाशय के नहर कार्य हेतु.
		रा.नि.मं.	294	0.030	
		विक्रमपुर.	295	0.200	
			297	0.170	
			312	0.070	
			310	0.080	
			310	0.110	
			310	0.200	
			310	0.180	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			309	0.260		
			291	0.040		
			209	0.070		
			215	0.160		
			216	0.020		
			166	0.110		
		योग निजी भूमि		<u>1.780</u>		
		शासकीय भूमि				
		311,308,307		<u>0.290</u>		
		कुल योग . .		<u>2.070</u>		

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)-2011-12-288-ए—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

### संशोधित अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/तालुका	नगर/ग्राम	सर्वे	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकमा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	शर्मापुर	निजी भूमि		कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी।	गोरखपुर जलाशय सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य (निजी भूमि)
		प. ह. नं. 18	15	2.78		
		रा.नि.मं.	16	1.38		
		शाहपुर.	17	1.07		
			19	1.86		
			20	1.10		
			21	1.45		
			22	1.64		
			24	2.61		
			32/1	0.59		
			32/2	0.60		
			33	1.30		
			9	0.16		
			11/1	0.15		
			11/2	0.14		
			12/2	0.07		
			13	0.42		
			44	0.08		
						नहर कार्य (निजी भूमि)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			45	0.26		
			47/1	0.07		
			47/2	0.07		
			57	0.18		
			58	0.18		
			59	0.31		
			61/2	0.03		
			62	0.13		
			63	0.17		
		योग . .		<u>18.80</u>		
			14	0.29		गोरखपुर जलाशय सिंचाई
			18	0.25		परियोजना शीर्ष कार्य
			23	0.29		(शास. भूमि)
			25	0.10		
			26	0.32		
			27	4.32		
			28	0.66		
			29	2.76		
			30	0.17		
			31	0.11		
			34	0.26		
			8	0.07		नहर कार्य (शास. भूमि)
			14	0.05		
			46	0.08		
			48	0.08		
			49	0.03		
			61/1	0.03		
		योग . .		<u>9.87</u>		
		कुल योग . .		<u>28.67</u>		

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिणडौरी में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जी. व्ही. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 30 अप्रैल 2012

क्र. 1594-भू-अर्जन-2012-राजस्व पत्रक क्र. अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के

अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(4)		
(1)	(2)	(3)	4.04	(5)	(6)	
झाबुआ	थान्दला	सेमलिया	योग	4.04	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग	ढोलखरा तालाब की नहर निर्माण हेतु.
					क्र. 1, झाबुआ.	

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी थान्दला के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 1596-भू-अर्जन-2012-राजस्व पत्रक क्र. अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			क्षेत्रफल भूमि (हे. में)	(4)		
(1)	(2)	(3)	6.10	(5)	(6)	
झाबुआ	थान्दला	रन्नी	योग	6.10	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग	ढोलखरा तालाब की नहर निर्माण हेतु.
					क्र. 1, झाबुआ.	

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी थान्दला के कार्यालय में देखा जा सकता है।

झाबुआ, दिनांक 1 मई 2012

क्र. 1631-भू-अर्जन-2012-राजस्व पत्रक क्र. अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			क्षेत्रफल भूमि (हे. में)	(4)		
(1)	(2)	(3)	0.35	(5)	(6)	
झाबुआ	थान्दला	नौगांव कालिया	योग	0.35	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग	ढोलखरा तालाब की नहर निर्माण हेतु.
					क्र. 1, झाबुआ.	

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी थान्दला के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 1633-भू-अर्जन-2012-राजस्व पत्रक क्र. अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	थान्दला	नौगांवां सोमला योग	2.72 2.72	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, झाबुआ.	ढोलखरा तालाब की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी थान्दला के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 1635-भू-अर्जन-2012-राजस्व पत्रक क्र. अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	थान्दला	नौगांवां नगला योग	2.31 2.31	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, झाबुआ.	ढोलखरा तालाब की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी थान्दला के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 1637-भू-अर्जन-2012-राजस्व पत्रक क्र. अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	थान्दला	कुकड़ीपाड़ा योग	5.91 5.91	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, झाबुआ.	ढोलखरा तालाब की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी थान्दला के कार्यालय में देखा जा सकता है।

झाबुआ, दिनांक 3 मई 2012

पत्र क्र. 1533-भू-अर्जन-2012-रा. प्र. क्र. अ-82-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	टेमरिया	0.07 योग	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद	माही परियोजना की रामगढ़ सब माईनर नं.-1 निर्माण हेतु. जिला-झाबुआ (म. प्र.)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 1535-भू-अर्जन-2012-रा. प्र. क्र. अ-82-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	छायनपश्चिम	1.31 योग	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद	माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर निर्माण हेतु. जिला-झाबुआ (म. प्र.)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 1537-भू-अर्जन-2012-रा. प्र. क्र. अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित

व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	घुघरी	0.69 योग 0.69	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद जिला-झाबुआ (म. प्र.)	माही परियोजना के रानीसिंग बैराज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

खरगोन, दिनांक 1 मई 2012

क्र. 615-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	महेश्वर	पिपल्याखुर्द	0.170 योग 0.170	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-20, मण्डलेश्वर।	ओंकारेश्वर परियोजना की द्वितीय चरण की दांयी तट मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

नोट.—(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 30 मई 2011	(1)	(2)
	411/2क	0.008
	410/2क	0.004
	420/1/1	0.020
	420/1/3	0.020
क्र. 727-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	419/1/3	0.016
	411/3	0.016
	410/3	0.008
	379/2	0.020
	367	0.024
	365	0.020
	419/1/1	0.012
	411/1	0.012
(1) भूमि का वर्णन—	410/1क	0.008
(क) जिला—रीवा	378	0.020
(ख) तहसील—मऊगंज	368	0.008
(ग) ग्राम—उमरी श्रीपति, ज. नं. 74	364	0.008
(घ) क्षेत्रफल—1.166 हेक्टर.	योग . .	1.166

## अनुसूची-2

खसरा नं.	अर्जित रकम (हेक्टर में)	ग्राम-उमरी श्रीपति, ज. नं. 74	
(1)	(2)		
307/2/1	0.101	452/3	0.202
306/2/1	0.202	451/1	0.082
307/2/2	0.101	434/3	0.105
306/2/2	0.202	445/1	0.202
286	0.012	446/1	0.129
285	0.020	447/3	0.202
284/2	0.016	434/4	0.203
284/1	0.016	434/5	0.405
283/1	0.020	436/1	0.040
284/3	0.016	220	0.020
281/2	0.016	222	0.082
281/3	0.016	315	0.090
281/4	0.016	317	0.116
281/5	0.016	316	0.045
438/1	0.040	251	0.164
438/3	0.012	219	0.024
437/1ख	0.020	187/1	0.028
356	0.016	218/1	0.060
421/1	0.048	218/3	0.040
420/1/2	0.020	189	0.074
419/1/2	0.016	218/4	0.028

(1)	(2)	(1)	(2)
218/5	0.028	37/4	0.008
187/2	0.008	37/1/2	0.008
182/1	0.062	योग . .	<u>0.380</u>
30	0.008		
182/2/1	0.040		
52	0.024		
51	0.030	04	0.353
182/3	0.020	17/2	0.085
31	0.040	17/3	0.096
57/1	0.040	28/2	0.410
57/2	0.040	योग . .	<u>0.944</u>
53/2	0.008		
53/1	0.004		
32	0.004	62	0.008
33	0.004	66/1	0.020
34	0.004	64	0.024
35	0.004	66/2	0.020
25/1	0.040	65/1	0.012
25/2	0.010	65/2	0.012
25/3	0.010	योग . .	<u>0.096</u>
25/5	0.004		
25/6	0.004		
योग. .	<u>2.777</u>		

**अनुसूची-3****ग्राम-उमरी माध्यौ, ज. नं. 73**

144	0.128
141	0.008
140	0.024
39, 40, 41, 42, 43, 71	0.024
29/1, 35	0.024
38/1	0.026
38/3	0.004
38/4	0.034
38/2	0.004
28/1	0.012
28/2	0.012
28/3	0.012
29/2	0.012
29/4	0.004
37/3	0.024
37/2	0.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैः—बेलहा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं नहर का निरीक्षण कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

रीवा, दिनांक 23 अप्रैल 2012

क्र. 135—भू—अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू—अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—त्योंथर

(ग) ग्राम—छदहना

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.936 हेक्टर.

खसरा नं. (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
325/1क	0.162
327/1	0.535
321/2	0.012
325/2क	0.202
327/2	0.769
325/3क	0.162
327/3	0.900
316/3	0.110
328/66	0.126
219	0.004
316/1	1.611
309	0.071
273	0.012
216/2	0.015
181	0.008
182	0.008
230	0.012
241	0.012
235	0.020
236	0.120
238	0.020
239	0.025
248	0.020
<hr/> योग . .	
	<u>4.936</u>

(ग) ग्राम—महेबा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—34.869 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	कुल रकबा (हेक्टर में) (2)	अर्जित भूमि (हेक्टर में) (3)
99	1.062	0.400
100	2.715	1.200
101	9.105	2.134
110/1	8.196	3.353
111/1	0.809	0.809
111/2	0.639	0.639
111/3	0.643	0.643
111/4	0.639	0.639
111/5	0.910	0.910
111/6	0.910	0.910
111/7	0.910	0.910
111/8	0.607	0.607
111/9	0.607	0.607
111/10	0.607	0.607
111/11	1.823	1.823
112/1क	0.909	0.909
112/1ख	1.315	1.315
112/1ग	1.315	1.315
112/1घ	0.909	0.909
112/1ड	1.215	1.215
112/2	0.405	0.405
113/1क	4.626	0.834
113/1ख	2.023	
113/2	6.070	2.100
114/1	4.552	2.160
114/2	4.552	2.140
136/1	1.444	0.028
136/4	0.579	0.012
112/515/1	6.030	2.015
112/615/2	0.405	0.405
597/1क	8.094	2.340

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—त्योंथर

क्र. 137-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1).में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
98/1	2.425		48/1	3.121	
98/2क/1	0.474		48/2क	0.030	
98/2क/2	0.809		48/2ख	0.010	
98/2ख/1	0.405	0.576	48/3	0.809	
98/2ख/2	0.365		48/4	2.023	
98/2ख/3	0.770		48/5क	2.023	
98/2ख/4	0.416		48/5ख	6.071	0.357
योग . .	<u>80.289</u>	<u>34.869</u>	48/6	0.607	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैः—जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग रीवा के अन्तर्गत शंकरपुर तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण कार्य।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 139-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—त्योंथर
- (ग) ग्राम—शंकरपुर
- (घ) क्षेत्रफल लगभग —1.584 हेक्टर।

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
67	6.925	0.220
73	8.619	0.220
74/1	3.642	0.051
74/2	2.428	0.035
74/3क	1.214	0.204
74/3ख	10.526	
78	0.360	0.067
79	0.362	0.060
81	0.336	0.032
82	0.283	0.032
84	0.299	0.062
85/1	0.425	0.010

48/7	0.202	
48/8	0.607	
48/9	0.526	
48/10	0.081	
41/1क	0.983	
41/1ख	1.446	
41/2	2.428	
41/3	2.023	
41/4	0.809	0.091
41/5	1.720	
41/6	6.070	
41/7	0.709	
41/8	4.047	
44/1	0.405	0.052
44/2	1.946	
45/1क	0.365	
45/1ख	0.30	
45/2	0.486	
45/3	0.405	0.091
45/5	0.121	
45/6	0.121	
योग . .	<u>75.732</u>	<u>1.584</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैः—जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग रीवा के अन्तर्गत शंकरपुर तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण कार्य।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

कटनी, दिनांक 3 अप्रैल 2012

क्र. 4-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन की इस बात का समाधान हो चुका है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—कटनी
- (ख) तहसील—रीठी
- (ग) ग्राम—सैदा, प.ह.नं. 29, नं. बं. 404
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.59 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	
(1)	(2)	
1234/1418	0.15	
1226/1420	0.45	
204/1	0.17	
1222/3	0.33	
1227/1419	0.06	
334/1426	0.26	
1222/2	0.17	
योग . .	1.59	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—लीपरी जलाशय योजना अन्तर्गत.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कटनी, के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 5-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन की इस बात का समाधान हो चुका है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—कटनी
- (ख) तहसील—रीठी
- (ग) ग्राम—मढ़ादेवरी, प.ह.नं. 29, नं. बं. 320
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—5.11 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
20/1	0.81
20/3	0.35
20/5	0.80
20/8	0.60
20/2	0.80
20/4	0.70
20/7	0.75
135/1	0.30
योग . .	5.11

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—लीपरी जलाशय योजना अन्तर्गत.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कटनी, के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अशोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.**

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

विदिशा, दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्र. 2-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूचित के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित

व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
  - (क) जिला—विदिशा
  - (ख) तहसील—शमशाबाद
  - (ग) ग्राम—ड़फरथाईकलौं
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल—5.013 हेक्टर.

सर्वे नम्बर.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
212	0.120
213	0.120
214	0.135
215/1	0.153
215/2	0.183
215/3	0.014
404/2	0.230
404/1	0.079
405/1	0.120
405/2	0.060
285	0.320
286	0.152
287	0.155
301/2	0.418
293/1	0.149
293/2	0.362
294	0.021
396/2	0.030
396/3	0.220
398/2	0.250
398/3	0.120
398/4	0.274
402	0.220
335	0.200
332	0.452
331/1	0.350
330/2/2घ	0.100
योग . .	<u>5.007</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—सापन उद्वहन सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटरन/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूचित के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
  - (क) जिला—विदिशा
  - (ख) तहसील—शमशाबाद
  - (ग) ग्राम—सारसी
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.366 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
	46
	<u>0.366</u>
	योग . . <u>0.366</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—सापन उद्वहन सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटरन/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 8-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूचित के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—शमशाबाद

(1)	(2)	(1)	(2)
(ग) ग्राम—रूसल्ली		320	0.097
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.450 हेक्टर.		319/3	0.028
सर्वे नम्बर	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में)	319/2	0.079
(1)	(2)	319/1	0.006
18	0.090	318	0.006
19	0.090	316/4	0.038
20	0.171	316/1	0.022
26	0.090	316/2	0.009
25/1	0.061	205/1	0.136
25/2	0.035	207/1	0.038
24	0.006	208	0.006
5/2	0.097	209/2	0.067
5/1	0.100	210	0.071
2/1	0.009	262	0.067
79/3	0.032	261	0.006
79/1	0.009	239	0.025
79/2	0.281	238	0.025
76/2	0.087	237	0.019
345	0.093	236	0.006
347	0.009	635	0.119
298/1	0.006	636	0.142
299/1	0.058	638/1	0.006
293	0.058	662/2	0.051
297/1	0.084	663	0.022
297/2	0.019	664/2	0.061
395	0.054	664/1	0.045
407	0.152	665	0.077
291	0.032	666	0.009
390	0.090	556	0.116
424/1	0.051	581/2	0.022
425/2	0.061	585/2	0.032
425/1	0.006	584	0.006
427	0.022	585/1	0.009
149/2	0.032	628	0.012
149/1	0.077	627/1	0.048
148/2	0.100	615/2	0.051
126/2	0.064	618/2	0.041
126/1	0.064	618/3	0.032
124/1	0.113	619/2	0.032
123	0.006	619/1	0.025
122/2	0.077	620	0.048
122/1	0.132	712/5	0.064
		173/1	0.093

(1)	(2)	(1)	(2)
715/1	0.048	354/1	0.179
716/5	0.006	356/2क	0.010
719/1/2	0.058	356/2ख	0.045
717	0.084	356/3	0.087
718	0.123	359/3क	0.020
721/2	0.116	350	0.140
722	0.116	336	0.014
712/6	0.041		
711	0.035	योग . .	<u>1.208</u>
709	0.129		
669/2	0.158		
योग . .	<u>5.450</u>		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है सापन उद्वहन सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 9-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूचित के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—  
 (क) जिला—विदिशा  
 (ख) तहसील—शमशाबाद  
 (ग) ग्राम—पाली  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.208 हेक्टर।

सर्वे नम्बर	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
224	0.034
240	0.110
316/1क	0.061
316/1घ	0.039
333/1	0.136
338/1	0.058
338/2	0.133
341/1	0.081
341/2	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है सापन उद्वहन सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 44-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूचित के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—  
 (क) जिला—विदिशा  
 (ख) तहसील—शमशाबाद  
 (ग) ग्राम—नसरतगढ़  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.433 हेक्टर।

सर्वे नम्बर	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
46/1/2	0.046
46/2ख/2	0.025
46/2ख/3	0.092
76/1/2	0.062
76/1/3	0.038
76/1/4क	0.071
76/1/5	0.074
76/1/6	0.025
योग . .	<u>0.433</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है सापन उद्वहन सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटरन/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है।	(1)	(2)
	260/2	0.022
	326/1	0.113
योग . .		1.674

प्र. क्र. 46-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—  
 (क) जिला—विदिशा  
 (ख) तहसील—शमशाबाद  
 (ग) ग्राम—डंगरवाड़ा  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.674 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
321/15	0.042
321/16	0.058
327	0.097
330/1	0.136
328/1क/1	0.009
328/1क/2	0.019
328/2/1	0.006
330/2	0.006
329/1	0.123
329/2	0.055
360/1ग	0.107
360/1क/3	0.019
360/1ख/3	0.035
362	0.077
363	0.129
368	0.019
367	0.019
370	0.077
372/1	0.006
372/2	0.006
310	0.133
311	0.087
263	0.071
262	0.070
260/1	0.133

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—सापन उद्वहन सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु.  
 (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटरन/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 50-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—  
 (क) जिला—विदिशा  
 (ख) तहसील—शमशाबाद  
 (ग) ग्राम—डफरयाईकलॉ  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.065 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
4	0.042
7	0.107
9	0.032
11	0.050
12	0.049
14	0.130
15	0.150
45	0.084
44	0.064
43	0.020
46	0.014
47	0.026
327/1/1	0.030
317/1/2क/1क	0.160
317/2	0.042
317/3	0.026
317/4	0.039

योग . . 1.065

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—सापन उद्वहन सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नटरन/शमशाबाद/गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
मनावर, दिनांक 18 अप्रैल 2012

क्र. 653-वाचक-प्र. क्र.-15-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार  
(ख) तहसील—मनावर  
(ग) ग्राम—कुण्डी (पूरक)  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.140 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकमा (हेक्टर में)
(1)	(2)
77/2	0.640
78/2	0.500
योग :	1.140

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ऑकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी., आर. डी. 145675 मी. से निकलने वाली कुण्डी डायरेक्ट माईनर 73 की टेल माईनर के बीच नहर निर्माण हेतु।

(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन की कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है।

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 659-वाचक-प्र. क्र.-20-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार  
(ख) तहसील—मनावर  
(ग) ग्राम—लिम्बी (पूरक प्रकरण)  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.997 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकमा (हेक्टर में)
(1)	(2)
231/2	0.580
270/1/2	0.012
97/3	0.190
291/1/1	0.100
15, 16/1घ	0.105
135/4	0.010
योग :	0.997

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ऑकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 127840 मी. से निकलने वाली डी. व्हाय 13 एवं उसकी माईनरों के निर्माण हेतु।

(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन की कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है।

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 665-वाचक-प्र. क्र.-16-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत

इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—मनावर
- (ग) ग्राम—पटवार (पूरक प्रकरण)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.847 हेक्टर.

संख्या	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1) 109/1/5	0.180
103/1	0.225
103/2/3	0.225
57/1/1क	0.275
65/1ख	0.180
65/3	0.132
62	0.110
109/2/2	0.080
110/2	0.440
योग :	<u>1.847</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ऑकरेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. डी. व्हाय. 12 की वितरण नहर एम.एल.-5 की आर. डी. 250 से 2705 मी. तक एवं उपनहरों के निर्माण हेतु.
- (3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन की कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं

पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 24 अप्रैल 2012

क्र. क-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 11-अ-82-10-11.—चूंकि,  
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई

अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
- (ख) तहसील—बण्डा
- (ग) ग्राम—कंदारी
- (घ) क्षेत्रफल—09.84 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
-----------	------------------------

(1)	(2)
54/1	0.14
55	0.40
62	0.16
63	0.01
68	0.03
69	0.12
70	0.10
76	0.01
77	0.04
78	0.03
79	0.04
80	0.12
81	0.03
83	0.03
100	0.04
124	0.08
125/1	0.16
125/3	0.77
133	0.02
673/1	0.08
673/3	0.20
673/4	0.14
673/5, 673/6	0.15
674, 675	0.60
677	0.10
678	0.35
679	0.25

(1)	(2)
707	0.18
708	0.48
713	0.20
714	0.02
715	0.02
721	0.60
722	0.01
725/1	0.02
725/3	0.30
727	0.03
730/1	0.45
730/2	0.50
735	0.27
736	0.10
737	0.01
780	0.30
781	0.18
783/1	0.22
783/2	0.24
784	0.18
785	0.05
786	0.02
793/2	0.48
793/3	0.35
794/1	0.15
794/2	0.01
883	0.07
884	0.15
885	0.05

योग : 9.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बीला फीडर नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2 सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र.-2, सागर जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
रीवा, दिनांक 25 अप्रैल 2012

क्र. 900-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—गुढ़
- (ग) ग्राम—बहेरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.158 हेक्टर.

खसरा	अर्जित रकमा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
44	0.094
80	0.064
योग : <u>0.158</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना बांध के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर निर्माण में आने वाले निजी भूमि/शासकीय भूमि के सम्पत्तियों के अर्जन हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 902-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—खोखरा	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.242 हेक्टेयर.	37/2	0.013
खसरा	अर्जित रकबा	38
नम्बर	(हेक्टेयर में)	87
(1)	(2)	98
96	0.192	99
59	0.050	100/1
योग :	<u>0.242</u>	100/2
		101
(2)		108/1
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना बांध के अन्तर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाइ योजना की मुख्य नहर निर्माण में आने वाले निजी भूमि शासकीय भूमि के सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.	0.039	
(3)		108/2
भूमि का नक्शा (प्लान) का प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	139	
		182
		योग : <u>1.156</u>

पत्र क्र. 906—भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—त्योंथर
- (ग) ग्राम—घोड़िडहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.156 हेक्टेयर.

खसरा	रकबा	खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)	नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(1)	(2)
28	0.050	255	0.084
29	0.043	256/1	0.072
30	0.040	256/2	0.024
31	0.057	257	0.336
32	0.110	258/1, 258/2,	
33	0.052	258/2डी, 258/3	0.076
34	0.052	258/4, 258/4डी	
35	0.050	258/5	
36/1	0.023		
36/2	0.023		
37/1	0.013		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर उद्वहन सिंचाइ योजना के मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान)का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 908—भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—त्योंथर
- (ग) ग्राम—बुदामा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.627 हेक्टेयर.

(1)	(2)	(1)	(2)
273	0.051	(ग) ग्राम—डीह	
275	0.072	(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.380 हेक्टेयर.	
276/2	0.252	खसरा	रकबा
414	0.017	नम्बर	(हेक्टेयर में)
416	0.010	(1)	(2)
417/1	0.081	1212	0.067
417/2	0.199	1213	0.011
418	0.302	1216	0.010
419/1	0.206	1218	0.120
491/2	0.210	1219	0.010
448/1	0.004	1222	0.094
448/2	0.004	1223	0.171
453	0.141	1225	0.034
454	0.080	1306	0.004
455/1	0.022	1307	0.160
455/2	0.082	1308	0.50
456/1	0.005	1313	0.240
456/2	0.005	1314	0.004
458/1	0.071	1322	0.140
458/2	0.070	1323	0.050
459	0.151	1324	0.015
योग : <u>2.627</u>		1325	0.096
		1326	0.206
		1367	0.043

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 910—भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—त्योंथर

1368	0.007
1369	0.150
1376	0.011
1378	0.007
1379	0.077
1380	0.015
1381	0.072
1382	0.050
1383	0.029
1384	0.024
1390	0.003
1391	0.006
1392	0.010
1393	0.010
1394	0.040
1395	0.050
1396	0.094
1397	0.031

(1)	(2)	एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—
1411	0.020	
1412	0.205	
1413	0.159	
1414	0.002	(1) भूमि का वर्णन—
1415	0.115	(क) जिला—रीवा
1416	0.080	(ख) तहसील—त्योंथर
1417	0.024	(ग) ग्राम—खाम्हा
1428	0.016	(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.910 हेक्टेयर.
1429	0.032	खसरा
1656	0.120	नम्बर (हेक्टेयर में)
1683	0.020	(1) 214
1684	0.026	216
1685	0.048	222
1686	0.064	223
1693	0.013	224
1695	0.010	265
1696	0.096	262
1697	0.007	263
1698	0.115	259
1699	0.134	246
1700	0.090	245
1701	0.023	242
1708	0.030	130
	योग : <u>3.290</u>	131 0.255
		132 0.064
		129 0.113
		128 0.030
		127 0.025
		126 0.067
		501 0.005
		502 0.208
		513 0.131
		514 0.098
		512 0.051
		511 0.031
		564 0.231
		565 0.080
		566 0.005
		567 0.303
		568 0.005
		617 0.439
		618 0.058

**म. प्र. शासन**

1249	0.050
1393	0.010
1708	0.030
	योग : <u>0.090</u>
	कुल योग : <u>3.380</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु,

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 912-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक

**अनुसूची**

## (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—त्योंथर

(ग) ग्राम—खाम्हा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.910 हेक्टेयर.

खसरा रकबा

नम्बर (हेक्टेयर में)

(1) 214 (2)

216 0.096

222 0.130

223 0.140

224 0.200

265 0.130

262 0.106

263 0.128

259 0.335

246 0.115

245 0.075

242 0.005

130 0.077

131 0.255

132 0.064

129 0.113

128 0.030

127 0.025

126 0.067

501 0.005

502 0.208

513 0.131

514 0.098

512 0.051

511 0.031

564 0.231

565 0.080

566 0.005

567 0.303

568 0.005

617 0.439

618 0.058

(1)	(2)
619	0.018
620	0.057
621	0.093
623	0.264
624	0.289
633	0.112
<b>निजी भूमि :</b>	
292	4.790
510	0.020
	0.100
<b>शासकीय भूमि:</b>	
	0.12
<b>महायोग :</b>	
	4.910

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर का निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 914-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—त्योंथर
- (ग) ग्राम—खूँथी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.395 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रक्बा (हेक्टेयर में) (2)
1 दुमट	0.016
4 दुमट III	0.110
5	0.036
6 दुमट III	0.033
9	0.004
25 भूरा 1	0.044
26 भूरा 1	0.063
27/1 दुमट	0.089
3	कुल योग : 0.395

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 916-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—त्योंथर
- (ग) ग्राम—गीधा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.240 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	रक्बा (हेक्टेयर में) (2)
5/1	0.118
5/2	0.002
6	0.033
7/1	0.047
7/2	0.047
18	0.016
35/1	0.056
35/2	0.055
68	0.108
69	0.108
70	0.146
73	0.024
74	0.064
36/1	0.105
36/2	0.105
37/1	0.008
67	0.008
75	0.079
76	0.046
83	0.065

कुल योग : 1.240

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्वोंथर उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नवशा (प्लान)निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

रीवा, दिनांक 28 अप्रैल 2012

क्र. 938-प्रशा.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना  
 (ख) तहसील—रामपुर बघेलान  
 (ग) ग्राम—चोरमारी  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.471 हेक्टेयर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)

#### निजी खाता

(1)	(2)
961	0.048
966	0.032
965	0.254
964	0.016
934	0.187
933	0.024
932	0.058
931	0.024
930	0.389
929	0.016
916	0.423
<b>योग :</b> <u>1.471</u>	

(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है।  
 (3) बाणसागर परियोजना पुरबा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु।  
 (4) भूमि का नवशा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

रीवा, दिनांक 4 मई 2012

क्र. 1012-प्रशा.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना  
 (ख) तहसील—रामपुर बघेलान  
 (ग) ग्राम—बगहाई कोठार  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—10.887 हेक्टेयर.  
 खसरा रकबा  
 नम्बर (हेक्टेयर में)

#### निजी खाता

(1)	(2)
963	0.244
1039	0.312
965	0.016
945	0.014
946	0.082
944	0.029
942	0.155
941	0.012
940	0.088
939	0.064
928	0.368
927	0.138
926	0.142
855	0.176
856	0.160
839	0.104
829	0.144
826	0.080
825	0.152
824	0.080
823	0.056
822	0.224
821	0.168
801	0.160
545	0.184
546	0.144
539	0.060
538	0.038
525	0.237
526	0.144
527	0.013
567	0.013
502	0.076
501	0.112
454	0.020
500	0.048
455	0.006
498	0.072

(1)	(2)	(1)	(2)
458	0.001	211	0.096
463	0.160	213	0.036
464	0.012	212	0.192
450	0.032	232	0.408
418	0.123	233	0.016
417	0.006	234	0.344
416	0.028	242	0.016
419	0.040	241	0.011
415	0.016	243	0.034
411	0.016	244	0.058
412	0.016	245	0.072
414	0.012	257	0.016
371	0.040	367	0.056
372	0.004	368	0.016
373	0.078	164	0.065
365	0.088	160	0.047
364	0.014	161	0.078
363	0.058	162	0.010
362	0.012	158	0.014
165	0.038	157	0.108
166	0.026	154	0.108
167	0.104	152	0.035
170	0.086	116	0.022
171	0.009	117	0.144
174	0.072	118	0.022
175	0.040	125	0.058
178	0.088	121	0.050
182	0.088	119	0.050
192	0.104	105	0.202
191	0.101	102	0.007
193	0.043	78	0.245
196	0.028	79	0.004
195	0.030	80	0.014
197	0.072	81/1052	0.468
200	0.096	81	0.173
202	0.056	82	0.007
204	0.120	61	0.180
207	0.064	60	0.014
208	0.104	56	0.156

(1)	(2)	(1)	(2)	(3)
59	0.030	184/1	0.286	
57	0.014	184/2	0.288	0.103
53	0.220	177	2.686	0.012
52	0.173	27	1.249	0.011
51	0.166	34/1	0.296	
49	0.043	34/2	0.296	0.192
48	0.050	34/3	0.097	
43	0.079	34/4	0.498	
योग : 10.887				कुल अशासकीय भूमि : 0.378
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है— परियोजना पुरवा नहर के अंतर्गत आने वाली फैसला पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.				

- (2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकवा शेष नहीं है।
- (3) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 4 मई 2012

क्र. 1014-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
- (ग) ग्राम—खारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—०.३७८ हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	कुल रक्का (हेक्टेयर में) (2)	अर्जित भूमि (हेक्टेयर में) (3)
193	0.231	0.019
200	0.805	0.041

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के अंतर्गत आने वाली निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाण सागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1028-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना  
 (ख) तहसील—रामपुर बाघेलान  
 (ग) ग्राम—महुरछ कन्दैला  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.160 हेक्टेयर.  
 खसरा अर्जित रकबा  
 (हेक्टर में)

(1)	(2)
निजी खाता	
250 में से	0.145
234 में से	0.015
कुल अर्जित रकवा.	0.160

(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है।

(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर की महरछ माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु।

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुर्वांस बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1030-प्रशा.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामपुर बाधेलान

(ग) ग्राम—तपा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.307 हेक्टेयर.

खसरा	भूमि का क्षेत्रफल	अर्जित रकवा
नम्बर	(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)

### निजी खाता

(1)	(2)	(3)
891/2ड	0.020	0.019
891/2च/1	0.008	
892/1	0.551	0.288
892/2	0.547	
कुल अर्जित रकवा :		<u>0.307</u>

- (2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकवा शेष नहीं है।
- (3) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के तपा माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि/शेष भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु।
- (4) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु।
- (5) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुर्वांस बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2012

क्र.-2983-दस-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित प्रयोजन

के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जा सकता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अनूपपुर

(ख) तहसील—पुष्पराजगढ़

(ग) ग्राम—बहपुर, बहपुरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.269 हेक्टर.

खसरा	अर्जित रकवा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
49/424	1.214
97/4	0.133
331/3	0.720
340/4	0.202
योग :	
	<u>2.269</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन.—नोनघटी जलाशय निर्माण द्वाब क्षेत्र की भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व पुष्पराजगढ़, जिला—अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
दतिया, दिनांक 26 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 01-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—दतिया

(ख) तहसील—दतिया

(ग) ग्राम—उपरांय		(1)	(2)
(घ) अर्जित क्षेत्रफल—0.14 हेक्टर.		2034	0.03
खसरा	रकबा	2063	0.04
नम्बर	(हेक्टेयर में)	2064	0.08
(1)	(2)	2062	0.10
694/1	0.14	2066	0.04
	योग : 0.14	2068	0.08
		2071	0.10
		2079	0.02
		2080	0.04
		2081	0.03
		2082	0.20
			योग : 2.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—राजधान परियोजना के अंतर्गत दतिया सिंचाई नहर की विस्तारित की 1 एल माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 02-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—दतिया
- (ख) तहसील—दतिया
- (ग) ग्राम—भागौर
- (घ) अर्जित क्षेत्रफल—2.42 हेक्टर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1980	0.45
1982	0.08
1986	0.06
1985	0.12
1987	0.03
1988	0.04
1998	0.06
1999	0.10
2041	0.08
2033	0.03
2040/1	0.12
2040/2	0.05
2037	0.16
2038	0.02
2036	0.16
2035	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत गोपालपुरा नाला की नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 03-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—दतिया
- (ख) तहसील—दतिया
- (ग) ग्राम—खैरा
- (घ) अर्जित क्षेत्रफल—2.51 हेक्टर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
589	1.12
601	0.37
611	0.64
612	0.38
	योग : 2.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत गोपालपुरा नाला के निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 04-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—दतिया
- (ख) तहसील—दतिया
- (ग) ग्राम—सुमावली
- (घ) अर्जित क्षेत्रफल—2.25 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
138	0.58
46	0.06
45	0.45
44	0.43
388	0.73
योग : 2.25	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत कासना नाला के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—दतिया
- (ख) तहसील—दतिया
- (ग) ग्राम—राजपुर
- (घ) अर्जित क्षेत्रफल—0.83 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
363	0.57
366 Min.	0.26

योग : 0.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत कासना नाला के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—दतिया
- (ख) तहसील—दतिया
- (ग) ग्राम—काम्हर
- (घ) अर्जित क्षेत्रफल—1.17 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
212	0.13
263	0.02
213	0.01
294	0.02
245	0.12
244	0.11
260	0.02
261	0.06
262	0.06
247	0.02
256	0.08
257	0.07
295	0.45

योग : 1.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत कासना नाला तालाब की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः—

<b>अनुसूची</b>		(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि		370	0.03
(क) जिला—दतिया		369	0.25
(ख) तहसील—दतिया		171	0.18
(ग) ग्राम—सनौरा		349	0.10
(घ) अर्जित क्षेत्रफल—0.52 हेक्टर.		124	0.01
		351	0.24

खसरा	रकबा	(1)	(2)
नम्बर	(हेक्टेयर में)		
(1)		331	0.12
2	0.21	305	0.15
3	0.12	330	0.16
4	0.15	328	0.04
8	0.04	329	0.02
	<b>योग : 0.52</b>	306	0.12
		333	0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत कासना नाला तालाब की नहर निर्माण हेतु.	170	0.15
	176	0.18
	121	0.14
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.	120	0.15
	169	0.05
	168	0.02

प्र. क्र. 08-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः—

<b>अनुसूची</b>		(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि		108	0.12
(क) जिला—दतिया		107	0.18
(ख) तहसील—दतिया		85	0.24
(ग) ग्राम—राजपुर		84	0.12
(घ) अर्जित क्षेत्रफल—4.38 हेक्टर.		196	0.05
		195	0.05

खसरा	रकबा	(1)	(2)
नम्बर	(हेक्टेयर में)		
(1)		201	0.22
419	0.03	200	0.32
421	0.10	211	0.12
422	0.04		
424	0.04		
119	0.05		
425	0.02		
83	0.02		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत कासना नाला की नहर के निर्माण हेतु.	योग : 4.38
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.	

प्र. क्र. 09-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि	(2)	(1)	(2)
(क) जिला—दतिया		238	0.05
(ख) तहसील—दतिया		237	0.04
(ग) ग्राम—ढांकरी		236	0.04
(घ) अर्जित क्षेत्रफल—5.74 हेक्टर.		255	0.02
खसरा	रकबा	244	0.03
नम्बर	(हेक्टेयर में)	259	0.04
(1)	(2)	256	0.04
465	0.09	261	0.12
460	0.03	241	0.06
447	0.05	242	0.02
459	0.02	234	0.12
448	0.05	207	0.08
710	0.25	205	0.05
709	0.02	204	0.25
449	0.30	689	0.02
450	0.10	202 Min.	0.02
451	0.15	701	0.10
452	0.05	702	0.04
453	0.20	700	0.12
298	0.16	703	0.18
292 Min.	0.28	711	0.18
307	0.07	466	0.03
310	0.12	309	0.01
311 Min.	0.25	246	0.02
405	0.02	708	0.10
406	0.02	717	0.02
235	0.14	योग : 5.74	
312	0.15		
398	0.15		
388	0.02		
399	0.02		
401	0.14		
389	0.03		
396	0.15		
392	0.06		
393	0.08		
394	0.03		
391	0.12		
333	0.10		
336/1	0.18		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बुदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत कासना नाला तालाब की नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 10-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)

में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—दतिया
- (ख) तहसील—दतिया
- (ग) ग्राम—बरौदी
- (घ) अर्जित क्षेत्रफल—6.29 हेक्टर.

खसरा	रकबा	(1)	(2)
नम्बर	(हेक्टेयर में)	218/1	0.05
(1)	(2)	218/2	0.02
765	0.05	210/1	0.20
766	0.15	210/3	0.07
767	0.04	199	0.03
761	0.01	194	0.02
760	0.10	218/4	0.07
665	0.05	220	0.12
764	0.08	420	0.12
611	0.04	595	0.07
762	0.28	596	0.02
599	0.30	209	0.22
763	0.03	397	0.06
744	0.31	208	0.16
673	0.18	207	0.07
672	0.01	201	0.60
667	0.18	202	0.04
613	0.06	योग : 6.29	
594	0.15		
612	0.08		
610	0.14		
600	0.13		
424	0.06		
563	0.10		
564	0.08		
417	0.16		
593	0.06		
418	0.22		
415	0.18		
423	0.27		
403	0.10		
404	0.11		
400	0.02		
392	0.01		
230	0.02		
458	0.45		
395	0.03		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत कासना नाला तालाब की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—दतिया
- (ख) तहसील—दतिया
- (ग) ग्राम—नौनेर
- (घ) अर्जित क्षेत्रफल—9.86 हेक्टर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2250/1	0.02
2244	0.13

(1)	(2)	(1)	(2)
2250/2	0.10	1033	0.01
2249	0.06	1034	0.12
2263	0.02	906	0.14
2248	0.15	909	0.04
2268	0.20	876	0.15
2271	0.02	910	0.17
2284	0.07	911	0.07
2272	0.04	912	0.12
2269	0.04	875	0.09
2270	0.02	789	0.17
2280	0.08	787/1	0.08
2279	0.09	786	0.10
2278	0.01	788	0.08
2290	0.11	785	0.10
2291	0.11	478	0.02
2351	0.04	510	0.01
2352	0.16	477	0.04
2353	0.01	261	0.09
2120	0.18	239	0.46
2119	0.12	479	0.60
2122	0.08	481	0.04
2276	0.08	489	0.03
2147	0.30	424	0.02
2146	0.10	423/2	0.06
2133/1	0.15	496/2	0.10
2134	0.05	497/2	0.07
2135	0.10	497/1	0.07
1436	0.04	509	0.26
2136	0.28	508/4	0.01
2130	0.01	508/5	0.02
1508	0.05	508/6	0.02
1510	0.05	507	0.25
1512	0.12	495	0.02
1507	0.05	538	0.06
1511	0.09	537	0.01
1513	0.12	535	0.12
1515	0.03	534	0.06
1517	0.01	539/1	0.06
1516	0.07	539/2	0.02
1518	0.01	540	0.03
1031	0.28	541/1	0.02

(1)	(2)	इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—
541/2	0.01	अनुसूची
533	0.01	
528/1	0.09	
527	0.06	
295	0.02	
296	0.14	
299	0.18	
302	0.02	
298	0.02	
2151	0.04	
1030	0.18	
792	0.12	
899	0.06	
801	0.01	
260	0.15	
300	0.03	
301	0.10	
285	0.09	
283	0.06	
305	0.08	
281	0.08	
282	0.14	
248	0.06	
259	0.25	
योग : 9.86		
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत कासना तालाब की नहर के निर्माण हेतु।	
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्टर दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।	
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक देशवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।		
कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		
ग्वालियर, दिनांक 28 अप्रैल 2012		
प्र. क्र. 12-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को		
1024	0.293	0.108
1026	0.533	0.029
1036	0.920	0.112
1037	0.920	0.018
1038	1.411	0.005
1052	4.107	0.299
1053	2.571	0.239
1057	1.400	0.190
1058	2.090	0.118
1061/1	0.711	
1061/2	0.711	
1061/3	0.721	0.357
1063 मिन	0.366	
1063 मिन	1.379	0.138
1064	1.714	0.109

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1065	0.261	0.069	1255	1.641	0.370
1068 मिन	1.212	0.179	1256	0.867	0.011
1068 मिन	1.212		1257 मिन	1.118	0.386
1071 मिन	0.131	0.058	1257 मिन	0.930	
1071 मिन	0.130		1261	0.815	0.003
1117	0.836	0.166	1269	5.320	0.375
1129 मिन	0.888		1270	1.505	0.206
1129 मिन	1.464	0.325	1278 मिन	0.544	0.257
1129 मिन	1.464		1278 मिन	0.544	
1129 मिन	0.888		1267	1.756	0.122
1133	0.637	0.182	1279	0.742	0.197
1134	0.763	0.052	1280	1.494	0.303
1135	0.961	0.273	1281	0.669	0.123
1136	0.627	0.099	1286	2.372	0.643
1137	0.867	0.118	1288	1.181	0.093
1138	1.536	0.003	1390 मिन	0.627	0.195
1141	1.170	0.154	1390 मिन	2.038	
1142	0.742	0.194	1391	1.024	0.110
1147	1.756	0.309	1392	0.972	0.213
1148	0.711	0.047	1393	0.732	0.058
1191/1	0.418		1405/1 मिन	0.501	
1191/2	0.818	0.257	1405/1 मिन	0.251	0.281
1191/3	0.206		1405/2	0.742	
1192	0.251	0.060	1408	1.212	0.201
1194	0.627	0.065	1409	2.330	0.145
1195 मिन	0.620		1413	0.857	0.140
1195 मिन	0.620		1414	0.752	0.136
1195 मिन	0.620	0.388	1417 मिन	0.418	0.534
1195 मिन	0.627		1417 मिन	1.233	
1196	1.411	0.218	1418	1.035	0.201
1229	1.672	0.151	1419	0.491	0.188
1232/1	1.139	0.111	1420 मिन	0.653	0.013
1232/2	2.017	0.003	1420 मिन	0.63	
1237	2.017		1422 मिन	1.045	0.413
1238	2.644	0.330	1422 मिन	0.627	
1239 मिन	0.731		1437 मिन	0.606	
1239 मिन	0.732	0.096	1437 मिन	0.627	
1251	0.125	0.015	1438 मिन	0.606	0.116

(1)	(2)	(3)	(ग) ग्राम—जुझापुर	(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.979 हेक्टर.	
			सर्वे नं.	कुल रकबा (हे. मे.)	अर्जित रकबा (हे. मे.)
			(1)	(2)	(3)
1440	0.993	0.096			
1441/1	0.710				
1441/2	0.711	0.235			
1441/3	0.711		28	10.682	0.371
1450	1.003	0.179	56	9.761	0.445
1451	1.974	0.131	68	9.552	0.138
1453	0.721	0.026	69	0.690	0.098
1455/1	4.912	.	70	0.637	0.098
1455/2	4.322		71	0.835	0.115
1455/3	4.725	0.276	73	0.920	0.144
1455/4	3.135		74	1.871	0.127
1471	1.170	0.258	75	0.397	0.038
1472 मिन	0.810	0.036	78	2.247	0.207
1472 मिन	0.810		130	2.445	0.148
1487 मिन	0.836	0.292	133	0.920	0.198
1487 मिन	0.920		134	0.972	0.066
1488	1.233	0.072	141	2.769	0.381
1490	1.975	0.384	143	6.490	0.198
1492	2.268	0.021	145	1.390	0.191
1496	0.930	0.115	146	0.617	0.016
1497	1.693	0.115			
	योग . .	14.599		योग . .	2.979

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की डिस्ट्री. क्र. 04 एवं 05 के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 13-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर  
(ख) तहसील—चीनौर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की डिस्ट्री. क्र. 04 एवं 05 के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 14-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर  
(ख) तहसील—चीनौर

(ग) ग्राम—पीपरीपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.036 हेक्टर.

(ग) ग्राम—कोरतपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.069 हेक्टर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)	सर्वे नं.	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
23	0.554	0.073	9	4.902	0.345
24	1.703	0.036	14	0.920	0.070
148	0.596	0.094	15	7.326	0.818
150/1	1.771	0.047	52	5.164	0.339
150/2	2.222	0.058	55	5.696	0.315
152	1.223	0.025	173/1	0.919	0.041
160/1	3.303	0.110	173/2	0.920	0.041
160/2	0.857	0.029	175	1.202	0.312
160/3	0.982	0.033	179/1	0.659	0.053
162	1.651	0.113	179/2	1.860	0.150
164	2.999	0.281	181/1	0.988	0.030
165	1.254	0.137	181/2	0.988	0.030
	योग . .	<u>1.036</u>	181/3	0.987	0.029
			181/4	0.988	0.030
			195	5.090	0.224
			201	1.233	0.157
			202	0.742	0.144
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की डिस्ट्री क्र. 04 एवं 05 के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.		204	0.366	0.126
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.		208	1.599	0.113
			209	0.366	0.008
			220 मिन	0.437	0.011
			220 मिन	0.438	0.011
			221	1.003	0.173
			234 मिन	1.359	0.098
			234 मिन	0.784	0.056
			234 मिन	0.500	0.036
			234 मिन	0.500	0.036
			234 मिन	0.111	0.008
			234 मिन	0.500	0.036
			234 मिन	0.627	0.045
			234 मिन	0.50	0.036
			234 मिन	1.555	0.113
			236 मिन	0.500	0.019
			236 मिन	0.418	0.016
			योग . .	<u>4.069</u>	

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—चीनौर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की डिस्ट्री क्र. 04 एवं 05 के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.	(1)	(2)	(3)
	84/2	0.021	0.002
	85/1	0.888	0.108
	85/2	0.742	0.091
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.	316	6.636	0.294
	318/1	2.384	0.302
	318/2	2.392	0.303
	322 मिन	2.320	0.358
	322 मिन	2.320	0.359
	322 मिन	2.320	0.359
	323/1	1.489	0.489
	324/2	0.930	0.307
	335	5.489	0.429
	336/1	1.170	0.092
		योग . .	<u>6.695</u>

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
- (ख) तहसील—चीनौर
- (ग) ग्राम—लधवाया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—6.695 हेक्टर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
11	0.575	0.213
12	0.92	0.143
13/1	1.254	0.085
13/2	0.49	0.034
16 मिन	0.084	0.004
16 मिन	0.219	0.012
17 मिन	0.303	0.132
17 मिन	0.084	0.037
18	2.278	0.070
24	0.679	0.075
25	4.421	0.521
31	2.299	0.033
54	2.414	0.077
56	1.871	0.243
57	1.129	0.153
73/मिन-1	0.952	0.074
73/मिन-2	0.953	0.074
73/मिन-3	1.00	0.077
74/1	2.727	0.222
74/2	6.878	0.559
83	1.515	0.283
84/1	1.285	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की डिस्ट्री क्र. 04 एवं 05 के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 17-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
- (ख) तहसील—चीनौर
- (ग) ग्राम—बड़की सराय
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.969 हेक्टर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
906		4.668
907		0.969
910		2.729
913		1.703

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
914	0.639	0.168	25	0.867	0.139
915	0.136	0.005	26	1.641	0.212
916	0.815	0.019	74	4.467	0.212
917	0.648	0.061	77	1.536	0.207
918	2.926	0.370	78	2.696	0.386
928	1.599	0.349	79	1.442	0.115
929	1.108	0.083	80	2.571	0.020
931	1.609	0.070	135	1.076	0.127
1000	1.763	0.110	138	1.254	0.126
1002	1.766	0.073	139	4.096	0.120
	योग . .	<u>1.969</u>		योग . .	<u>2.217</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की डिस्ट्री क्र. 04 एवं 05 के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 18-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
- (ख) तहसील—चीनौर
- (ग) ग्राम—पुरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.217 हेक्टर।

सर्वे नं.	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
07	0.460	0.165
17	0.784	0.013
18	1.411	0.002
21	1.641	0.133
22	1.411	0.240

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की डिस्ट्री क्र. 04 एवं 05 के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 19-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
(ख) तहसील—चीनौर	396	0.345
(ग) ग्राम—फतेहपुर	397	0.193
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.75 हेक्टर।	398	0.146
	403	0.066
	योग :	<u>0.75</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की डिस्ट्री क्र. 04 एवं 05 के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.	(1)	(2)	(3)
	234	0.261	0.013
	263/1	2.591	0.279
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.	263/2	1.611	
	272	0.690	0.293
प्र. क्र. 20-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	273	0.230	0.100
	292/1	0.979	0.179
	292/2	1.463	
	292/3	1.463	
	293	4.965	0.078
	294/1	0.607	0.705
	294/2	1.127	
	294/3	1.128	
(1) भूमि का वर्णन—	295/1	0.758	0.324
(क) जिला—ग्वालियर	295/2	0.511	
(ख) तहसील—चीनौर	295/3	2.079	
(ग) ग्राम—ऐराया	295/4	1.983	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.303 हेक्टर.	297/1क	1.860	0.198
सर्वे नं.	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित रकबा (हे. में.)	
(1) 94	(2) 0.167	(3) 0.011	297/1 क मिन 1.860
99	0.439	0.013	326 0.188 0.019
100	0.178	0.090	329 2.006 0.522
101	0.690	0.039	330 3.292 0.502
121	0.084	0.047	336 1.327 0.166
122	0.178	0.063	339 0.408 0.032
149/1	0.198	0.163	340 0.909 0.228
149/2	0.168		350 0.063 0.039
150	0.031	0.007	363 मिन 0.292 0.077
151/1	0.105	0.003	363 मिन 0.261
151/2	0.104		363 मिन 0.094
177	0.303	0.024	363 मिन 0.042
196	0.073	0.009	365 1.076 0.306
197	0.428	0.194	366/1 0.168 0.415
198	0.158	0.007	366/2 मि 0.209
199	0.115	0.062	366/2 मि 0.209
207	0.115	0.019	375 0.461 0.027
232	0.324	0.091	376 0.219 0.049
233	0.272	0.093	399 0.899 0.067
			400 0.418 0.153
			401 0.010 0.010

(1)	(2)	(3)
402	0.721	0.040
403	0.826	0.147
405/1	0.888	
405/2मि	0.167	0.253
405/2मि	0.209	
492	1.423	0.350
500	0.742	0.005
502	0.345	0.055
503	0.972	0.366
504/1	1.076	0.166
504/2	1.076	
558	0.878	0.055
561	0.721	0.150
योग . .		7.303

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की डिस्ट्री क्र. 04 एवं 05 के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2012

क्र. 01-अ-82-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—राजनगर

(ग) नगर/ग्राम—बमीठ

(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.098 हेक्टेयर।

खसरा	रकबा
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)
96/1/ख	2.098

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—इण्डियन रेल्वे केटरिंग एण्ड ट्रॉज़िम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन की आवश्यकता है।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय राजनगर में किया जा सकता है।

छतरपुर, दिनांक 7 मई 2012

प्र. क्र. 11-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—लवकुशनगर

(ग) ग्राम—कटहरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—3.870 हेक्टेयर।

खसरा	अर्जित रकबा
क्रमांक	(हे. में)
(1)	(2)
278	0.192
385	0.086
548	0.007
481	0.016
612	0.090
686	0.158
684	0.050
685	0.226
551	0.396
615	0.151
616	0.172
280	0.144
283	0.005

(1)	(2)
281	0.152
760	0.156
757	0.064
252	0.250
274	0.486
547	0.450
683	0.035
759	0.237
755	0.052
758	0.295
योग : <u>3.870</u>	

(2) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 14-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—लवकुशनगर
- (ग) ग्राम—रनमऊ
- (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—1.925 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
127	0.237
126	0.084
128	0.020
137	0.295
130	0.130
121	0.188
118, 119	0.324
125	0.259

(1)	(2)
131	0.324
117	0.064
योग : <u>1.925</u>	

(2) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 15-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—लवकुशनगर
- (ग) ग्राम—देवपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—2.286 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
572	0.080
573	0.304
521	0.128
547	0.210
522	0.028
499	0.090
540	0.140
520	0.010
565	0.130
564	0.116
566	0.010
546	0.210
563	0.210
530	0.170
526	0.320
500	0.130
योग : <u>2.286</u>	

(2) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत नहर प्रणाली हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 16-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—लवकुशनगर

(ग) ग्राम—मड़वा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—2.677 हेक्टेयर।

खसरा	अर्जित रकबा
क्रमांक	(हे. में)
(1)	(2)
23	0.201
24	0.097
35	0.044
37	0.420
45	0.247
62	0.517
63/1	0.206
63/2	0.068
199	0.144
218	0.028
216	0.024
217	0.086
219	0.256
220	0.086
222	0.201
225	0.016
226	0.036
योग : <u>2.677</u>	

(2) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 17-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—लवकुशनगर

(ग) ग्राम—बगमऊ

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.745 हेक्टेयर।

खसरा	अर्जित रकबा
क्रमांक	(हे. में)
(1)	(2)
218	0.019
220	0.105
221	0.093
222	0.020
233	0.010
232	0.120
234	0.024
217/1	0.043
235/2	0.100
217/2	0.115
219	0.096
योग : <u>0.745</u>	

(2) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 19-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—लवकुशनगर

(ग) ग्राम—मुड़ेरी उचरी		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—1.920 हेक्टर.		777	0.100
खसरा	अर्जित रकबा		
क्रमांक	(हे. में)	759	0.150
(1)	(2)	698	0.010
296	1.140	700	0.200
294	0.528	656	0.056
291	0.240	657	0.030
293	0.012	551	0.256
	योग : <u>1.920</u>		
(2) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत नहर प्रणाली हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।		667	0.240
		658	0.076
(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है।		497	0.104
		500	0.112
		502	0.015
प्र. क्र. 20-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		666	0.104
		548	0.040
		688	0.184
		769	0.050
		552	0.112
		547	0.092
अनुसूची			
(1) भूमि का वर्णन—		550	0.010
(क) जिला—छतरपुर		558	0.080
(ख) तहसील—चंदला		671	0.060
(ग) ग्राम—नगरौली		689	0.010
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—3.748 हेक्टर.		495	0.200
खसरा	अर्जित रकबा		
क्रमांक	(हे. में)	496	0.076
(1)	(2)	553	0.090
498	0.124	687	0.010
546	0.080		
758	0.020		
686	0.180		
703	0.200		
545	0.016		
668	0.010		
659	0.090		
771	0.480		
772	0.081		
	योग : <u>3.748</u>		
(2) सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत नहर प्रणाली हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।			
(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है।			
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,			

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

डिण्डौरी, दिनांक 30 अप्रैल 2012

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12-280-ए.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—डिण्डौरी
- (ग) ग्राम—रकरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.28 हेक्टर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
<b>बांधी तट नहर कार्य</b>	
423	0.05
424	0.15
425	0.19
450	0.07
463	0.05
464	0.03
466	0.13
<b>दांधी तट नहर कार्य</b>	
277	0.02
278	0.32
299	0.10
300	0.17
योग निजी भूमि . .	<u>1.28</u>
शासकीय भूमि—	<u> </u>
451, 459, 462, 280	0.37
योग शासकीय भूमि . .	<u>0.37</u>
कुल योग . .	<u>1.65</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रकरिया जलाशय स्कीम के अंतर्गत नहर कार्य हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12-281-ए.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—डिण्डौरी
- (ग) ग्राम—पलकी माल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—7.93 हेक्टर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)

**शीर्ष कार्य**

117/3	0.10
118	0.61
119	0.20
120	0.55
124	0.26
125	0.17
129/1	1.15
157	0.81
158	0.65
159	0.20
<b>बांधी तट नहर कार्य</b>	
1	0.40
4	0.12
5	0.12
8	0.15
9	0.17
11	0.14
12	0.32
15	0.60
26	0.31
27	0.05
103	0.02
106/1	0.18
106/2	0.09
107	0.02
108	0.21

(1)	(2)	(1)	(2)
113	0.20	316/1	0.280
117/3	0.13	320	0.100
योग निजी भूमि . .	<u>7.93</u>	321	0.040
शासकीय भूमि—		346	0.190
126, 127, 128, 156,	4.83	347	0.140
6, 14, 24, 101, 116		348/1	0.030
योग शासकीय भूमि . .	<u>4.83</u>	348/2	0.300
कुल योग . .	<u>12.76</u>	349/2	0.120
		358	0.280
		359	0.200

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रकरिया जलाशय स्कीम के अंतर्गत नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12-282-ए.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—डिण्डौरी
- (ग) ग्राम—नरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—5.61 हेक्टर.

खसरा	अर्जित रकमा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)

#### नहर निजी भूमि

266	0.160
267	0.260
270	0.120
276	0.190
286	0.150
287	0.130
291	0.070
293	0.060
294	0.100
295	0.150
296	0.150
313	0.080
314	0.140

316/1	0.280
320	0.100
321	0.040
346	0.190
347	0.140
348/1	0.030
348/2	0.300
349/2	0.120
358	0.280
359	0.200
360	0.130
361/1	0.240
217	0.060
219/1	0.030
221	0.020
226	0.050
227/2	0.110
228	0.030
230	0.030
361/1	0.140
361/2	0.090
367	0.080
368	0.030
369	0.060
370	0.140
190	0.120
191	0.080
192	0.020
197	0.160
198	0.020
204	0.120
239	0.080
240	0.050
241	0.060
244	0.180
348/1	0.020
361/1	0.020
योग निजी भूमि . .	<u>5.610</u>
नहर कार्य निजी भूमि—	
254, 268, 275, 278,	0.240
315, 319, 322, 364	
सकल योग . .	<u>5.850</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गोरखपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत दांवी तट नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12-283-ए.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—डिण्डौरी
- (ग) ग्राम—भरवई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.902 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
<b>दांयी नहर निजी भूमि</b>	
33	0.110
29	0.064
28/1	0.025
28/2	0.025
27	0.090
26	0.090
22	0.013
69	0.110
71	0.020
73	0.230
74	0.160
78	0.050
79	0.030
82	0.230
87	0.130
103	0.250
102	0.100
108/1	0.065
101	0.110
योग निजी भूमि . .	<u>1.902</u>
नहर कार्य निजी भूमि—	
39, 46, 70, 77, 84, 90, 100	0.113
सकल योग . .	<u>2.015</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गोपालपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत दांयी तट नहर कार्य हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12-284-ए.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—डिण्डौरी
- (ग) ग्राम—पड़िरियामाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.830 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
<b>बांयी नहर निजी भूमि</b>	
303	0.100
298/4	0.120
297	0.020
291	0.050
295	0.075
293	0.060
290	0.060
277/1	0.130
275/1	0.070
275/2	0.060
274	0.040
272	0.010
273	0.040
263	0.090
265	0.019
257/2	0.080
256	0.030
255	0.079
254	0.070
437	0.090
444	0.050
446	0.010
445	0.050
490	0.030
489	0.100
488	0.025
487	0.020
485	0.038
484	0.050

(1)	(2)	(ग) ग्राम—सारंगपुर
516	0.050	(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.386 हेक्टर.
517	0.036	खसरा अर्जित रकबा
515	0.079	नम्बर (हेक्टेयर में)
628/1	0.070	(1) (2)
627	0.030	नहर कार्य निजी भूमि
625/1	0.040	386 0.030
625/2	0.040	377 0.133
617	0.040	379 0.300
618	0.070	373 0.048
620	0.010	372 0.220
619	0.040	369 0.150
615	0.080	399 0.200
604	0.100	300 0.240
603	0.020	301 0.132
594	0.130	303 0.210
572	0.110	304/1 0.110
575	0.140	304/2 0.110
563	0.080	304/3 0.110
योग निजी भूमि . .	<u>2.830</u>	303 0.018
नहर कार्य निजी भूमि—		306/2 0.290
308, 296, 292, 280,	0.150	285/441 0.072
270, 451, 247, 481,		282 0.060
493, 629, 593, 571		283 0.030
सकल योग . .	<u>2.980</u>	279 0.040
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गोपालपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत बांधी तट नहर कार्य हेतु.		278 0.060
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.		277 0.030
क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12-285-ए.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-	276 0.040	
अनुसूची		275 0.070
(1) भूमि का वर्णन—		274 0.005
(क) जिला—डिण्डौरी		273 0.080
(ख) तहसील—डिण्डौरी		271 0.060
		270 0.050
		272 0.010
		269 0.040
		268 0.010
		267 0.150
		262 0.090
		261 0.030
		239/1 0.350
		239/2 0.070
		244 0.120
		176 0.200
		152 0.100
		153 0.015
		173 0.110
		172 0.110

(1)	(2)	(1)	(2)
161	0.100	160	0.200
162	0.190	162	0.070
112	0.090	163	0.100
370	0.020	165	0.200
372	0.190	183	0.060
373	0.050	184	0.060
364	0.027	186	0.280
400	1.130	योग निजी भूमि . .	<u>1.510</u>
401	0.710	नहर कार्य निजी भूमि	
377	0.576	143	0.020
योग निजी भूमि . .	<u>7.386</u>	कुल योग . .	<u>1.530</u>
नहर कार्य निजी भूमि			
392, 378, 370, 217, 309, 284, 265, 263, 242, 243, 182, 150, 370, 50	0.405		
कुल योग . .	<u>7.791</u>		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सांरगपुर पड़सिया जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर कार्य हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12-287-ए.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—डिण्डौरी
- (ग) ग्राम—सूरजपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.51 हेक्टर।

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
124/1	0.180		
137	0.240		
138	0.030		
142	0.090		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गोरखपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत बांधी तट नहर कार्य हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जी. वी. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 1 मई 2012

रा. प्र. क्र. 02-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बुरहानपुर
- (ख). तहसील—बुरहानपुर
- (ग) ग्राम—जाफरपुरा, दौलतपुरा, जसौंदी, रायसेना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—64.933 हेक्टर (बांध निर्माण एवं नहर निर्माण हेतु)।

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	(1)	(2)
197/1		ग्राम—दौलतपुरा (तालाब हेतु)	2.01
197/2			1.20

(1)	(2)	(1)	(2)
203/1	0.826	25	0.14
203/3	1.08	28	0.05
206	0.16	34	0.47
204	0.06	ग्राम-दौलतपुरा ( नहर कार्य हेतु )	
207	2.574	142	0.120
214	0.14	143	0.120
215	0.59	155	0.080
216	1.10	144/1	0.140
225	0.33	144/2	0.050
226/1	2.29	147	0.090
226/2	2.63	173	0.240
227/1	1.94	174	0.090
227/2	1.01	176	0.072
229	3.25	178	0.050
230	0.70	182/1	0.096
238	0.43	182/2	0.096
239	1.03	207	0.106
247/1	2.26	ग्राम-रायसेना	
247/2	1.79	73/3	0.060
250	0.58	72/4	0.048
251	1.96	72/3	0.096
254	1.05	71/2	0.216
252	1.49	70/4	0.048
258	0.29	70/3, 70/2	0.096
253	0.51	70/1	0.048
261	1.67	69	0.170
263/1	1.90	77	0.110
263/2	1.20	76/1	0.064
263/3	1.20	76/2	0.130
263/4	0.80	75	0.120
265/1	2.09	74	0.010
265/2	0.80	171/2	0.070
266	2.83	172	0.065
269	0.76	173/1	0.060
271	0.25	174	0.024
272/1	1.13	175	0.065
272/2	1.12	176	0.045
272/3	1.12	177	0.041
272/4	1.10	143	0.067
273	3.34	142	0.041
274	1.75	141/1	0.026
ग्राम-जाफरपुरा		141/2	0.024
22	0.35	139	0.050
24	0.09		

(1)	(2)	(1)	(2)
146	0.110	137/1	0.14
147	0.060	127	0.334
150/3	0.019	124/1	0.130
123	0.029	132/1	0.150
124/1	0.024	कुल योग . .	<u>64.933</u>
124/2	0.024		
125/1	0.072		
126	0.020		
<b>ग्राम-जसौंदी</b>			
88/1	0.064		
88/2	0.064		
89/1	0.060		
90/2	0.075		
97/2	0.012		
97/1	0.048		
91/1	0.085		
91/2	0.030		
107/2	0.050		
107/3	0.050		
107/4	0.030		
107/1	0.060		
109	0.130		
110/2	0.043		
110/1	0.200		
111/3	0.105		
135	0.264		
100/1	0.030		
100/2	0.036		
100/3	0.030		
123/1	0.130		
124/2	0.430	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा
125/1	0.115		(हेक्टर में)
125/2	0.062	(1)	(2)
196/1	0.100	ग्राम-धामनगाँव ( तालाब हेतु )	
126	0.154		
198	0.120	155/1	0.036
133/1	0.020	155/2	0.024
133/2	0.052	155/3	0.010
133/3	0.048	155/4	0.010
133/4	0.216	155/5	0.030
147	0.130	166	0.16
139	0.050	167	0.05
138	0.144	168	0.14
		169	0.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—अंजनडोह तालाब योजना का शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रा. प्र. क्र. 03-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बुरहानपुर
- (ख) तहसील—बुरहानपुर
- (ग) ग्राम—धामनगाँव, गोलखेड़ा, गोंधनखेड़ा, चापोरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—118.225 हेक्टर (बांध निर्माण एवं नहर निर्माण हेतु).

(1)	(2)	(1)	(2)
170	0.90	335	0.58
171	0.85	336	0.18
176	3.58	337	0.90
179	0.99	339/1	0.85
181	0.65	339/2	0.75
180	0.90	340/1	0.77
182	2.99	340/3	0.81
183	4.20	346	0.05
186	0.93	351	0.24
187	0.50	353	0.37
412	0.20	355	1.10
188	1.38	357	0.12
189	0.70	362/1	0.73
190	0.64	362/2	0.73
191/1	1.32	363/1	1.03
191/2	0.40	363/2	0.40
192	1.16	364	0.58
193	1.16	365	0.15
194/1	0.63	396	0.20
194/2	0.63	397/1	0.16
327	0.43	366	1.21
195/1	0.52	367	0.69
195/6	0.29	371/1	1.04
195/2	0.80	371/2	0.81
195/3	0.40	372/1	0.10
195/4	0.40	372/2	0.80
195/5	1.39	372/3	0.60
196	2.23	372/4	0.81
201/1	2.50	373/1	0.47
201/2	0.80	373/2	1.91
201/3	0.40	374	0.36
325	1.57	375/2	0.44
329	1.93	388	1.35
330/1	0.40	377	1.20
330/3	0.20	375/1	0.27
409	0.76	376	1.06
330/2	0.93	380	1.00
331	0.67	381	0.87
332	1.07	385/1	0.80
333	1.27	385/2	1.55
334	0.69	389/1	0.39

(1)	(2)	(1)	(2)
389/2	0.39	464	1.42
389/3	0.39	465	0.67
395	0.66	466	1.03
389/4	0.38	467	0.20
389/5	0.38	468	0.14
390	0.60	469/1	0.16
394	0.40	469/2	0.11
406	0.79	470	0.03
397/2	0.61	493	0.16
398	2.92	494	0.35
399	1.05	495	0.57
402	0.83	496	1.17
403	0.83	499	0.17
404	0.60	503/1	0.30
405/1	0.43	503/2	0.30
405/2	0.61	504/1	0.08
407	0.62	504/2	0.12
408	1.46		ग्राम-गोलखेड़ा
410	0.10	245	0.08
413	0.74	265	0.06
414	0.69	246	0.20
415	1.32	248/1	0.24
416/1	0.75	248/2	0.06
416/2	0.87	248/3	0.08
421	0.50	256	0.30
422	0.46	261	0.10
424	0.16	262	0.13
423	0.60	266	0.12
425	0.08	267	0.12
444	0.01	271	0.70
446/1	0.16	272	0.40
446/2	0.14	273/1	0.10
454	0.51	273/2	0.07
455	0.30		ग्राम-धामनगाँव ( नहर कार्य )
456/1	0.26	5/1	0.140
456/2	0.60	7/1	0.070
457	0.52	7/4	0.030
458	0.36	34	0.080
459	0.32	35	0.100
462	0.48	36	0.045
463	0.65		

(1)	(2)	(1)	(2)
37	0.045	299/2	0.080
38	0.210	299/4	0.032
42	0.110	303/1	0.022
65	0.038	303/2	0.022
67/1	0.038	303/3	0.057
69/1	0.102	304	0.044
83	0.020	305	0.032
92	0.134	306	0.072
237	0.120	307	0.072
93	0.256	308	0.025
111	0.100	271/5	0.120
112/1	0.050	309	0.038
112/4	0.050	310/1	0.016
113	0.080	310/2	0.016
114	0.090	271/2	0.070
116	0.100	271/3	0.080
118/3	0.055	271/4	0.060
118/2	0.045	ग्राम-चापोरा	
118/4	0.110	789	0.020
149	0.180	790	0.060
205/1	0.064	791	0.040
210/1	0.016	792	0.020
210/2	0.016	793	0.090
210/3	0.016	794	0.040
211	0.100	795	0.130
212	0.060	797	0.130
213	0.080	798	0.155
236	0.110	812/1	0.025
239/2	0.006	812/2	0.025
241	0.048	819/1	0.020
242	0.038	819/3	0.020
263	0.110	820	0.036
264/1	0.006	876/2	0.040
264/2	0.100	821	0.032
264/3	0.080	822	0.250
266/2	0.110	858	0.040
276/1	0.024	860	0.020
277	0.064	872/1	0.025
278	0.070	872/2	0.004
276/2	0.024	873	0.032
299/1	0.020	859	0.014

(1)	(2)	(1)	(2)
875	0.045	1276	0.120
877	0.040	1277/1, 1277/2	0.120
878	0.050	1278/1	0.050
897	0.270	1278/2	0.050
907	0.020	1280/2	0.180
920	0.020	1312	0.040
917/1	0.010	1308	0.050
917/2	0.020	1311	0.030
918	0.050	1309	0.030
919	0.050	1310	0.030
921	0.110	1313/1	0.060
922	0.050	1313/2	0.040
934/2	0.040	1314/1	0.080
934/3	0.040	1314/2	0.060
937/2	0.050	1358	0.110
944/1	0.080	1360	0.110
944/2	0.010	1361	0.010
945	0.100	ग्राम-गोंधनखेड़ा	
952	0.140	1120	0.020
946	0.030	1219/2	0.050
955, 956	0.080	1222/1	0.070
		1223	0.090
		1224	0.070
		1247/1	0.140
		1247/2	0.060
		1248	0.070
		1250	0.100
		1252/1	0.020
		1252/5	0.020
		1252/2	0.020
		1252/4	0.020
		1254/1	0.060
		1254/3	0.050
		1255, 1256	0.180
		1257, 1258	0.140
		1269/1	0.100
		1269/2	0.100
		1270	0.050
		कुल योग . .	
			118.225

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—धामनगाँव तालाब योजना का शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

खरगोन, दिनांक 1 मई 2012

क्र. 610-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—महेश्वर
- (ग) ग्राम—सुल्याखेड़ी
- (घ) क्षेत्रफल—5.788 हेक्टर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/2	0.020
1/3	0.080
3/1	0.260
3/3	0.160
3/6	0.530
7	0.415
8/2	0.445
8/5	0.230
50/1/1क 1	0.050
50/1/1क 2	0.005
50/1/1 क 3	0.425
50/2/1 क	0.440
50/1/1 क 4	0.546
50/2/1 ख	0.225
55/3	0.430
55/4	1.090
57/2	0.040
57/3	0.041
71/1	—
72/4	0.050
73/4	0.045
72/1	0.032
73/1	0.045
72/3	0.050
73/3	0.057

(1)	(2)
71/2	—
72/5	0.005
73/5	0.050
72/6	—
73/6	0.012
73/7	—
74/1	—
75/1	0.010
कुल . .	5.788

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ऑकरेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला-खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 611-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—महेश्वर
- (ग) ग्राम—मेलखेड़ी
- (घ) क्षेत्रफल—4.330 हेक्टर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
53/1	0.865
53/4	0.100
53/5	0.510
56	0.120
65/111	0.860
66	0.455
71/1/1	1.130
71/1/2,	0.290
72	—
कुल . .	4.330

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ऑकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.	(1)	(2)
	117/2	0.460
	125/1	0.725
	126/1	—
	127/1	0.355
	127/3	0.280
	126/3	—
	127/4	0.280
	127/5	0.220
	130/1	0.340
	131	0.390
	132	0.600
	144/1/1	0.960
	144/1/5	0.390
	143	—
	145	0.280
	कुल . .	<u>15.696</u>

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—महेश्वर
- (ग) ग्राम—बबलाई
- (घ) क्षेत्रफल—15.696 हेक्टर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
108/1/1	0.830
108/1/2	0.790
108/3	0.837
108/4	0.125
108/5	0.150
108/6	0.837
109/1	0.135
109/2	0.230
109/3	0.440
109/4/12	0.202
109/4/13	0.360
110	0.825
112	0.540
111	2.200
113	0.090
115/2	0.520
115/7	0.540
115/8	0.420
115/9	0.010
115/8/1	0.225
117/1	0.110
118	—

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ऑकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला—खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा, विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 613-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—महेश्वर
- (ग) ग्राम—भकलाय
- (घ) क्षेत्रफल—4.625 हेक्टर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
159/1	0.690
159/2	0.360
163	0.550
164	0.060
165	0.300
169/1	0.010

(1)	(2)	(1)	(2)
170/1क	0.600	56/1	0.140
170/1ख	0.040	56/2	0.250
170/3	0.325	56/3	0.170
176/1	0.025	56/4	0.220
176/2/2/1	0.240	63/2	0.440
176/2/2/2	0.150	63/3	0.380
176/2/2	0.135	64	0.700
176/2/1	0.255	65	0.220
180/1/1, 180/2/1	0.540	66/1/2	-
180/1/2, 180/2/2	0.345	66/2	0.040
कुल . .	<u>4.625</u>	92	-
		67/4	0.240
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.		69/2	0.630
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोबर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.		70/2	0.010
क्र. 614-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		69/3/1/2	0.010
		69/4	0.260
		71/1	0.115
		71/2	0.121
		71/3	0.121
		71/4	0.182
		72/1/6	0.020
		72/4/2	0.050
		73/1	0.340
		73/2	0.250
		98/1/1	0.025
		98/1/2	0.162
(1) भूमि का वर्णन—		98/2/1	0.073
(क) जिला—खरगोन		98/2/2	0.190
(ख) तहसील—महेश्वर		98/2/5	0.036
(ग) ग्राम—मक्षी		101/1	0.360
(घ) क्षेत्रफल—9.966 हेक्टर.		101/2	0.780
खसरा	रक्कड़ा	102/1	0.020
नम्बर	(हेक्टेयर में)	112/3	-
(1)	(2)	102/5	0.607
46/1	0.015	103/1	0.110
50/2	0.285	103/2	0.155
55/2	0.050	103/3	0.194

(1)	(2)
103/183/1,	0.085
103/183/2/1	
104/1	0.920
104/2	0.800
104/3	0.190
कुल . .	<u>9.966</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर उद्घाटन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इंदौर, दिनांक 2 मई 2012

क्र. 77-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—इंदौर
- (ख) तहसील—(महू) डॉ. अम्बेडकर नगर
- (ग) ग्राम—बशीपिपरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.424 हेक्टर।

खसरा	रकबा
क्रमांक	(हेक्टर में)
(1)	(2)
371/3	0.424
योग . .	<u>0.424</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैः—चोरल बांध पर आधारित सामुहिक जल प्रदाय योजना के लिए।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, तहसील (महू) डॉ. अम्बेडकर नगर एवं कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यात्रिकी खण्ड, इंदौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राघवेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 3 मई 2012

प्र. क्र. 1-(क) प्र. भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—कुरवाई
- (ग) ग्राम—लायरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.462 हेक्टर

कुल खसरा	क्षेत्रफल
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
1051/1/1	0.037
1051/1/2	0.038
1049, 1050/1	0.067
1052	0.167
1054/1	0.011
826/1	0.021
874	0.003
836/2	0.011
871	0.036

(1)	(2)
835/2	0.003
835/1/2	0.003
835/1/1	0.003
835/3	0.018
591/2	0.005
591/3/1	0.003
591/3/2	0.002
592/1	0.011
597	0.018
594/3	0.005
<b>कुल :</b> <u>0.462</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बीना-कुरवाई-सिरोंज मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई एवं जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3-(क) प्र. भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—कुरवाई
- (ग) ग्राम—इकौदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.732 हेक्टेयर

कुल खसरा	क्षेत्रफल
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
24/1/2	0.175
24/2/1	0.182
23/2	0.105
75/1	0.115
77/1	0.105
<b>कुल :</b> <u>0.732</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बीना-कुरवाई-सिरोंज मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई एवं जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4-(क) प्र. भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—कुरवाई
- (ग) ग्राम—केशरांज
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.058 हेक्टेयर

कुल खसरा	क्षेत्रफल
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
58/1/3	0.008
58/1/2 (क)	0.042
58/2/1	0.008
<b>कुल :</b> <u>0.058</u>	

उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—विदिशा
- (ख) तहसील—कुरवाई
- (ग) ग्राम—भौरासा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1 हेक्टेयर

कुल खसरा	क्षेत्रफल
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
955	0.082
954	0.125
951/1	0.523
947/1/1	0.365
<b>कुल : 1.095</b>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बीना-कुरवाई-सिरोंज मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई एवं जिला विदिशा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 7 मई 2012

क्र.-क्यू-भूमि संपादन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उज्जैन
- (ख) तहसील—घटिया

(ग) ग्राम—पानबिहार, रनाहेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—09.20 हेक्टेयर

खसरा	अर्जित रकमा
नम्बर	(हेक्टर में)

(1)	(2)
<b>ग्राम-पानबिहार</b>	

294/1, 294/3	0.95
--------------	------

294/2	0.61
-------	------

365 मी	0.05
--------	------

366	0.39
-----	------

361 मी	0.75
--------	------

369	0.11
-----	------

370	0.33
-----	------

योग :	<u>3.19</u>
-------	-------------

### ग्राम-रनाहेड़ा

424/6	1.60
-------	------

424/7	0.60
-------	------

424/8	0.15
-------	------

424/5	1.15
-------	------

424/1/2	1.00
---------	------

344	0.04
-----	------

345	0.10
-----	------

76/1	0.52
------	------

387	0.85
-----	------

योग :	<u>6.01</u>
-------	-------------

### ग्राम रनाहेड़ा के प्रभावित मकान का विवरण

खसरा	क्षेत्रफल	मकान का प्रकार
नम्बर	वर्गमीटर	
(1)	(2)	(3)
335	48.00 एवं 45.51	पक्का ईंट का छत चद्दर कच्चा मिट्टी का छत अंग्रेजी कवेलू
340	22.14	पक्का सीमेंट ईंट का छत चद्दर
324	56.25	पक्का सीमेंट रेत ईंट छत नहीं
292/2	42.33 एवं 9.13	पक्का ईंट का प्लास्टर सहित छत गर्डर फर्शी.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—तहसील घटिया शंकरपुर तालाब के कार्य/नहर हेतु अधिग्रहित अशासकीय भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, घटिया कोठी पेलेस, उज्जैन में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

**उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर**

जबलपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2012

क्र. 512-गोपनीय-2012-दो-3-1-2012 (भाग-बी).—न्यायिक अधिकारी जिनके नाम के पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में पांच दिवसीय प्रशिक्षण “Refresher Course for Civil Judges, Class-II” (2008 Batch) (Fifth Batch), जो दिनांक 25 जून 2012 से 29 जून 2012 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 25 जून 2012 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है।

**प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:—**

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा। समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तदनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें।
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 25 जून 2012 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित हों।
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित हों। महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित हों।
4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्न में से प्रत्येक की एक प्रति, प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के, कम-से-कम एक सप्ताह पूर्व, प्रशिक्षण संस्थान को अवश्य प्रेषित करें :—
  - (i) Judgment in Civil case (contested) and
  - (ii) Judgment in Criminal case (contested)
  - (iii) Issues framed by themselves
  - (iv) Charge framed by themselves
  - (v) Accused Statement prepared by themselves.
5. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे जिन विधिक समस्याओं/विषयों पर चर्चा चाहते हों, को प्रशिक्षण केन्द्र के फैक्स नं. 0761-2626945 पर समय रहते अग्रिम प्रेषित करें।
6. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं।
7. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा।
8. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक-1 के मुख्य द्वार पर वाहन की व्यवस्था की जावेगी, जो कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी। अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में प्रतः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें।
9. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी। यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी। इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी.ए. एवं डी.ए. क्लेम करने के पात्र होंगे।
10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

सुभाष काकड़े, रजिस्ट्रार जनरल।

जबलपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2012

क्र. C-3465.—श्री एस. के. साहा, रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ, जबलपुर की तर्दह पदोन्नति/नियुक्ति की अवधि दिनांक 1 मई 2012 से 30 जून 2012 तक दो माह के लिये इस रजिस्ट्री के आदेश क्र. बी/2906 जबलपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2011, आदेश क्र. बी/637, जबलपुर, दिनांक 29 फरवरी 2012 एवं आदेश क्र. डी/1590, दिनांक 29 मार्च 2012 के तारतम्य में बढ़ाई जाती है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

सुभाष काकड़े, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2012

क्र. B-918-तीन-10-42-75 (डिण्डोरी-शहपुर).—मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की

धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री सिद्धार्थ कुमार शर्मा, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, डिण्डोरी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश अपने घोषित कार्यस्थल डिण्डोरी के अतिरिक्त शहपुरा में भी प्रत्येक माह एक सप्ताह बैठक करेंगे।

No. B-918-III-10-42-75 (Dindori-Shahpura).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Shri Siddharth Kumar Sharma, IIInd Additional Judge to Civil Judge, Class-II, Dindori in addition to his place of sitting declared at Dindori shall also sit at Shahpura for one week in each month.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
अभय कुमार, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2012

क्र. बी-941-पेंशन-चार-9-4-39 भाग-तीन-डी.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं खण्डपीठ इन्दौर, ग्वालियर की स्थापना के निम्नलिखित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को उनकी अधिवार्षिकीय आयु आगामी वर्ष 2013 में पूर्ण करने के उपरान्त उनके नाम के सामने तालिका के स्तम्भ क्रमांक (5) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्ति किया जाता है :—

#### तालिका

क्रमांक	नाम	पदनाम एवं पदस्थापना	जन्मतिथि	वर्ष 2013 सेवानिवृत्ति का दिनांक वित्त विभाग, भोपाल के ज्ञापन क्र. 439/3497/75 आर.-एक-चार दि. 10-4-76 के अनुसार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

#### प्रथम श्रेणी अधिकारी

1 श्री एम. एच. कर्णिक	डिप्टी रजिस्ट्रार, उ.न्या., मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इन्दौर.	13-3-1953	31-3-13 अप.
-----------------------	--	-----------	-------------

#### द्वितीय श्रेणी अधिकारी

1 श्री एन. एस. लखेरा	अनुभाग अधिकारी, उ. न्या., मध्यप्रदेश, जबलपुर.	10-6-1953	30-6-13 अप.
2 श्रीमती मीना अल्बर्ट	अनुभाग अधिकारी, उ. न्या., मध्यप्रदेश, जबलपुर.	29-6-1953	30-6-13 अप.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	श्री गुलाम हुसैन	अनुभाग अधिकारी, उ. न्या., मध्यप्रदेश, जबलपुर.	27-10-1953	31-10-13 अप.
4	श्रीमती जयश्री खरे	अनुभाग अधिकारी, उ. न्या., मध्यप्रदेश, जबलपुर.	28-10-1953	31-10-13 अप.
5	श्रीमती सुमन विश्वकर्मा	अनुभाग अधिकारी, उ. न्या., मध्यप्रदेश, जबलपुर.	27-11-1953	30-11-13 अप.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
सुभाष काकड़े, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2012

क्र. बी-913-तीन-6-2-2012.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में वर्णित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेपः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है :—

### सारणी

क्रमांक (1)	न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी (2)	पदस्थापना का स्थान (3)	राजस्व जिला (4)
1	श्री राजेश जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दतिया	दतिया	दतिया
2	श्री माधवराव पटेल, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, उमरिया	उमरिया	उमरिया
3	श्री हरिशचन्द्र पटेल, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, उमरिया	उमरिया	उमरिया
4	श्रीमती नजमा बेगम, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, उमरिया	उमरिया	उमरिया
5	श्री प्रशांत शुक्ला, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड
6	श्री अवधेश श्रीवास्तव, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड
7	श्री राजकुमार चौहान, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जोबट, अलीराजपुर	जोबट	अलीराजपुर
8	सुश्री सपना भारती, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अलीराजपुर	अलीराजपुर	अलीराजपुर

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
अभय कुमार, रजिस्ट्रार.